वर्ष 12 • अंक 262 • 12 पृष्ठ • मूल्य 5 रुपये

शनिवार 21 दिसंबर 2019

कोलकाता, चंडीगढ़, **नई दिल्ली**, पटना, भोपाल, मुंबई, रायपुर और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार

बिज़नेस स्टैंडर्ड

www.bshindi.com

पृष्ठ 6

अगले साल भी महंगा बिकेगा आलू

गीता गोपीनाथ ▸▸ पृष्ठ 4

राजकोषीय मजबूती पर टिकी रहे सरकार

डॉलर रु. 71.10 ▲ 10 पैसे | यूरो रु. 78.90 ▼ 20 पैसे | सोना (10ग्राम) रु 37968 ▲ 91 रुपये | सेंसेक्स 41681.50 ▲ 07.60 | निफ्टी 12271.80 ▲ 12.10 | निफ्टी फ्यूचर्स 12290.00 ▲ 18.20 | ब्रेंट क्रूड 67.40 डॉलर ▼ 0.30 डॉलर

एक नज़र

फिच ने भारत की साख रखी बरकरार, घटाया अनुमान

फिच रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान 5 प्रतिशत से घटाकर 4.6 प्रतिशत कर दिया है। फिच ने कहा कि उसका मानना है कि इस समय कंपनियों और उपभोक्ताओं का विश्वास कमजोर हो रहा है। हालांकि एजेंसी ने देश की दीर्घकालिक वित्तीय साख 'बीबीबी' के स्तर पर बरकार रखी है और आगे का आर्थिक परिदृश्य स्थिर रखा है। फिच का अनुमान है कि साथ 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि 5.6 प्रतिशत और 2021-22 में 6.5 प्रतिशत तक जा सकती है। रेटिंग एजेंसी की राय में मौद्रिक एवं राजकोषीय नीतियों में ढील तथा अवसंरचनात्मक उपायों से वृद्धि दर में क्रमिक सुधार होगा।

झारखंडः त्रिशंकु विधानसभा के आसार, गठबंधन को बढ़त

झारखंड के विधानसभा चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिलने का अनुमान जताया गया है। शुक्रवार को अंतिम चरण के मतदान के बाद जारी एग्जिट पोल के अनुसार राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाला गठबंधन को सबसे अधिक 38-50 सीटें मिल सकती हैं। निवर्तमान मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व में भाजपा को 22-32 सीटें मिलने का अनुमान है। आजसू को 3-5 सीटें मिलने का अनुमान है। राज्य में मतगणना 23 दिसंबर को होगी। पृष्ठ 12

जेट एयरवेजः दिवालाशोधन प्रक्रिया अवधि 90 दिन बढ़ी

जेट एयरवेज की दिवाला एवं ऋण शोधन प्रक्रिया की अवधि 90 दिन बढ़ गई है। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) ने शुक्रवार को इसकी मंजूरी दे दी। दक्षिण अमेरिका की कंपनी सिनर्जी ग्रुप ने निर्णय करने के लिए अधिक समय की मांग की है। इसके अलावा दो अन्य इकाइयां भी जेट एयरवेज में दिलचस्पी दिखा रही हैं। कर्जदाताओं की समिति ने इसी के मद्देनजर एनसीएलटी की मुंबई पीठ से दिवाला एवं ऋणशोधन प्रक्रिया पूरी करने के लिए अवधि में विस्तार देने की मांग की थी। प्रक्रिया की 180 दिन की अवधि 16 दिसंबर को समाप्त हो चुकी है।

त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी ऐंड संस होगी दिवालिया

त्रिभुवनदास भीमजी जवेरी ऐंड संस रिटेल प्राइवेट लिमिटेड (टीबीजेडएसआर) ने दिवालिया के लिए आवेदन किया है। राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) के आदेश के बाद कंपनी ने यह कदम उठाया है। कंपनी मुंबई के ओपेरा हाउस में अपना एकमात्र आभूषण शोरूम बंद कर दिया है। एनसीएलटी ने टीबीजेडएसआर को निगमित ऋण शोधन समाधान प्रक्रिया (सीआईआरपी) शुरू करने की अनुमति दी थ्थी।

जॉनसन के ब्रेक्जिट विधेयक को सांसदों का मिला समर्थन

ब्रिटेन की संसद के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स में यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर होने संबंधी विधेयक पर अपनी मुहर लगा दी। सदन में यूरोपीय संघ (निकास समझौता) विधेयक को 358 सदस्यों का समर्थन मिला, जबकि 234 सदस्यों ने इसके खिलाफ मतदान किया। इस विधेयक में 31 जनवरी को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर आने का प्रावधान है। गुरुवार को पेश इस विधेयक पर अब संसद में आगे भी चर्चा होगी।

व्यापार गोष्ठी

सहकारी बैंकों की व्यवस्था कैसे हो दुरुस्त?

अपनी राय पासपोर्ट साइज फोटो और पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :

बिज़नेस स्टैंडर्ड , नेहरू हाउस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें gosthi@bsmail.in अपने विचार आप हमें bshindi.com पर भी भेज सकते हैं

आज का सवाल

दूसरी कंपनियों को भी उत्तराधिकार मामले में महिंद्रा से लेनी चाहिए सीख

www.bshindi.com **पर राय भेजें।**
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **BSP Y** और यदि न है तो **BSP N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा

क्या जीएसटी क्रेडिट पर बंदिश से बढ़ेगी उद्योग की मुश्किल	हां	66.67%
	नहीं	33.33%

5जी स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी

मार्च-अप्रैल में हो सकती है 5 लाख करोड़ रुपये की स्पेक्ट्रम नीलामी

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

- मार्च-अप्रैल तक **8300** मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की बिक्री **5.23** लाख करोड़ रुपये में होगी
- सफल बोलीदाताओं को करना होगा **1** गीगाहर्ट्ज से कम स्पेक्ट्रम के लिए **25** फीसदी अग्रिम भुगतान
- **1** गीगाहर्ट्ज से अधिक के लिए **50** फीसदी अग्रिम भुगतान

- अग्रिम भुगतान के बाद बाकी भुगतान में दो साल के स्थगन की सुविधा
- तीसरे साल से **16** सालाना किस्तों में शेष राशि का करना होगा भुगतान
- ट्राई ने देश भर के लिए प्रति मेगाहर्ट्ज **492** करोड़ रुपये आधार मूल्य की सिफारिश की

- **20** मेगाहर्ट्ज के ब्लॉक में होगी **3,300** से **3,600** मेगाहर्ट्ज के 5जी बैंड के स्पेक्ट्रम की नीलामी
- प्रीमियम **700** मेगाहर्ट्ज के लिए आधार कीमत **40** फीसदी से ज्यादा घटाकर **6,568** करोड़ रुपये की
- बीएसएनएल और रेलवे को आवंटित किए जाने वाले 4जी स्पेक्ट्रम नीलामी में नहीं होंगे शामिल

केंद्र सरकार ने स्पेक्ट्रम नीलामी के अगले चरण की तैयारी शुरू कर दी है। मार्च-अप्रैल में 8,300 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी से सरकार को 5.23 लाख करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है, वहीं संभावित बोलीदाताओं को राहत देते हुए भुगतान ढांचे को आसान बनाया गया है।

दूरसंचार विभाग का शीर्ष निर्णायक निकाय डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) ने आज सभी 22 सर्किलों के लिए नीलामी को मंजूरी दे दी। 5जी के लिए 6,050 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रखे गए हैं। सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान में ढील के साथ ही भुगतान में दो साल स्थगन की सुविधा दी गई है और बाकी रकम तीसरे साल से 16 साल तक वार्षिक किस्तों में चुकानी होगी।

दूरसंचार सचिव अंशु प्रकाश ने कहा, 'डीसीसी ने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सिफारिशों को आज मंजूरी दे दी और हमें उम्मीद है कि नीलामी मार्च-अप्रैल में हो सकती है।'

1 गीगाहर्ट्ज से कम स्पेक्ट्रम के लिए कुल रकम का 25 फीसदी अग्रिम भुगतान करना होगा, वहीं 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक के लिए 50 फीसदी अग्रिम रकम का भुगतान करना होगा। इसके साथ ही अगर सफल बोलीदाता की घोषणा के बाद 30 दिन के अंदर स्पेक्ट्रम उपलब्ध नहीं होता है तो 1 गीगाहर्ट्ज बैंड से कम पर अग्रिम भुगतान में 10 फीसदी और 1 गीगाहर्ट्ज से अधिक के लिए अग्रिम भुगतान में 20 फीसदी की रियायत दी जाएगी।

प्रकाश ने कहा, 'ऐसी स्थिति में कंपनियों को स्पेक्ट्रम आवंटन से एक महीने पहले बाकी अग्रिम राशि का भुगतान करना होगा।'

2020 की नीलामी दूरसंचार विभाग उन लाइसेंसी को भी स्पेक्ट्रम की पेशकश करेगा जिनके लाइसेंस की वैधता दिसंबर 2021 में खत्म हो रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) और रेलवे को आवंटित किए जाने वाले 4जी स्पेक्ट्रम को नीलामी से अलग रखा जाएगा।

ट्राई ने शुरुआत में 4.9 लाख करोड़ रुपये मूल्य के स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश की थी। दूरसंचार विभाग द्वारा 8 सर्किलों में रिलायंस कम्युनिकेशंस, भारती एयरटेल तथा वोडाफोन एवं आइडिया के 4-4 सर्किलों के लाइसेंस खत्म होने से मुक्त हुए स्पेक्ट्रम को भी नीलामी में शामिल करने से स्पेक्ट्रम की मात्रा में 150 मेगाहर्ट्ज से ज्यादा का इजाफा हो गया।

ट्राई ने 1 अगस्त, 2018 को 700 मेगाहर्ट्जर्स, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300-3400 मेगाहर्ट्ज और 3400-3600 मेगाहर्ट्ज बैंड में स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश की थी।

ई-नीलामी आयोजित करने के लिए एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए बोली आंमत्रित की जा चुकी है। इच्छुक एजेंसियां 13 जनवरी तक बोली जमा करा सकती हैं, जिसके बाद 24 जनवरी को वित्तीय बोली खोली जाएगी।

(शेष पृष्ठ 2 पर)

अर्थव्यवस्था की ढांचागत खामियां हुईं दूरः मोदी

नई दिल्ली में एसोचैम के 100वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।

शुभायन चक्रवर्ती
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

- बढ़ चढ़कर निवेश करें उद्योगपति
- 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य संभव
- अर्थव्यवस्था मौजूदा चुनौतियों से निकलने में सक्षम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि अर्थव्यवस्था की ढांचागत खामियों को दूर कर लिया गया है और भारत को 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए अब उद्योग जगत को बढ़चढ़कर निवेश करना चाहिए।

मोदी ने उद्योग संस्था एसोचैम के 100वें स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम को संबंधित करते हुए कहा कि आने वाले वर्षों में देश में ढांचागत सुविधाओं के विकास पर 100 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर 25 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि हर घर तक पेयजल पहुंचाने की योजना पर 3.5 लाख रुपये का निवेश होगा।

प्रधानमंत्री ने कहा, 'अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर जिस तरह की बातें हो रही हैं, उसके बारे में मुझे सब पता है। मैं इन बातों को चुनौती नहीं देता हूं बल्कि इनमें जो अच्छाई होती है उसे लेकर आगे बढ़ जाता हूं।' उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के समय एक तिमाही में आर्थिक वृद्धि की दर 3.5 फीसदी रह गई थी। खुदरा मुद्रास्फीति 9.4 फीसदी तक पहुंच गई थी। थोक मुद्रास्फीति का आंकड़ा 5.2 प्रतिशत और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के मुकाबले राजकोषीय घाटा 5.6 फीसदी तक पहुंच गया था।' विनिर्माण और उपभोक्ता खपत कमजोर पड़ने से जुलाई-सितंबर 2019 तिमाही में जीडीपी की विकास दर घटकर 4.5 फीसदी प्रतिशत रह गई जो मोदी सरकार के छह साल के कार्यकाल में सबसे कम है। मोदी ने कहा, 'मैं इस बहस में नहीं पड़ना चाहता हूं कि जो लोग आज बोल रहे हैं, वे तब चुप क्यों थे। अर्थव्यवस्था में पहले भी उतार-चढ़ाव आए हैं लेकिन आज देश इस आर्थिक सुस्ती और मौजूदा परिस्थितियों से बाहर निकलने में देश पूरी तरह समर्थ है।'

बैंकों को ज्यादा कर्ज बांटने का निर्देश

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकारी बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक के पास रिवर्स रीपो के रूप में ज्यादा पैसा रखने के बजाय ज्यादा कर्ज बांटने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि नकदी की किल्लत से सबसे अधिक जूझ रहीं गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को नकदी मुहैया कराई गई है। एसोचैम के कार्यक्रम में सीतारमण ने कहा कि एक बुनियादी ढांचा कोष के तहत कम से कम 10 परियोजनाओं की पहचान की गई है और उन्हें अग्रिम रकम मुहैया कराई जाएगी। सीतारमण ने कहा कि भारतीय कंपनियों को 'खुद पर संदेह' की मुद्रा से बाहर आना चाहिए। पृष्ठ 4

कार्यकारी चेयरमैन का पद छोड़ेंगे महिंद्रा

टी ई नरसिम्हन
चेन्नई, 20 दिसंबर

- 1 अप्रैल से बन जाएंगे गैर कार्यकारी चेयरमैन
- गोयनका के पास होगी एक साल के लिए सीईओ की अतिरिक्त जिम्मेदारी
- 1 अप्रैल, 2021 से आशीष शाह होंगे गोयनका के उत्तराधिकारी

वाहन क्षेत्र की दिग्गज कंपनी महिंद्रा ऐंड महिंद्रा (एमऐंडएम) उत्तराधिकार योजना के तहत अपने शीर्ष प्रबंधन में फेरबदल कर रही है। इसके मुताबिक समूह के कार्यकारी चेयरमैन आनंद महिंद्रा अगले साल 1 अप्रैल से गैर कार्यकारी चेयरमैन की भूमिका में होंगे। फिर से प्रबंध निदेशक नियुक्त किए गए पवन कुमार गोयनका के कंधों पर 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए मुख्य कार्याधिकारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी होगी।

एमऐंडएम ने आज एक बयान में कहा कि उसकी कामकाज, नामांकन और पारिश्रमिक समिति (जीएनआरसी) ने बोर्ड और वरिष्ठ प्रबंधन के पुनर्गठन का फैसला किया है। कंपनी ने सीईओ पद बनाया है क्योंकि वह इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की योजनाओं को लागू कर रही है और निकट भविष्य में फोर्ड के भारतीय परिचालन के साथ तालमेल पर ध्यान दे रही है।

गोयनका का कार्यकाल 1 अप्रैल, 2021 तक है और उसके बाद एमऐंडएम के ग्रुप प्रेजिडेंट (रणनीति) आशीष शाह उनकी जगह लेंगे। शाह 1 अप्रैल, 2020 से एक साल के लिए मुख्य वित्त अधिकारी बनेंगे और वह अप्रैल 2021 से चार साल के लिए एमऐंडएम के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्याधिकारी होंगे। उनका कार्यकाल 31 मार्च, 2025 तक होगा।

कंपनी ने कहा कि गैर-कार्यकारी चेयरमैन के रूप में महिंद्रा संरक्षक की भूमिका निभाएंगे और खासकर रणनीतिक योजना जैसे मामलों में निदेशक मंडल को मजबूती प्रदान करेंगे। 1 अप्रैल, 2020 से राजेश जेजुरीकर कार्यकारी निदेशक (वाहन एवं कृषि क्षेत्र) के तौर पर एमऐंडएम निदेशक मंडल में शामिल होंगे। उनके पास वाहन एवं कृषि क्षेत्र के परिचालन की जिम्मेदारी होगी। वह पहले गोयनका को और फिर शाह को रिपोर्ट करेंगे। टेक महिंद्रा के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी सी पी गुरनानी गैर-कार्यकारी निदेशक के तौर पर एमऐंडएम निदेशक मंडल से जुड़ेंगे। ग्रुप प्रेजिडेंट मानव संसाधन एवं कॉरपोरेट सर्विसेज और मुख्य कार्याधिकारी (बिक्री बाद सेवा) राजीव दुबे अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त होंगे और उसके बाद भी गैर कार्यकारी और सलाहकार के तौर पर समूह से जुड़े रहेंगे। आनंद महिंद्रा ने कहा, 'इस योजना से पता चलता है कि एमऐंडएम प्रबंधन में प्रतिभाओं से भरा है। नया प्रबंधन सुनिश्चित करेगा कि समूह की संस्कृति, मूल्य, कामकाज और परिचालन कुशलता आगे भी बरकरार रहे। अपनी नई भूमिका में मैं खुद को महिंद्रा समूह के सजग प्रहरी के रूप में देखता हूं। आंतरिक ऑडिट मुझे रिपोर्ट करता रहेगा। मैं निदेशक मंडल पर नजर बनाए रखूंगा।'

नागरिकता कानूनः विरोध प्रदर्शन की कारोबार पर मार

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

- चांदनी चौक, भागीरथ प्लेस, चावड़ी बाजार में कारोबार ठप
- पहाडगंज, करोलबाग के किफायती होटलों में कम हुई कमरों की बुकिंग
- विरोध प्रदर्शन से मेट्रो सेवा प्रभावित होने से भी कारोबार पर बुरा असर

दिल्ली में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहे विरोध-प्रदर्शन की मार कारोबार पर भी पड़ने लगी है। कारोबार के अहम केंद्र पुरानी दिल्ली के बड़े बाजारों में बिक्री सुस्त हो गई है। सबसे ज्यादा मार चांदनी चौक, भागीरथ प्लेस, चावड़ी बाजार और जामा मस्जिद के आसपास के कारोबारों पर पड़ी है। दिल्ली के किफायती होटलों में कमरों की बुकिंग भी कम हो रही है।

चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के महासचिव संजय भार्गव ने कहा कि चांदनी चौक में दुकानें तो खुली हैं, लेकिन कारोबार नदारद है। भार्ग ने कहा, 'गुरुवार को कारोबार ना के बराबर हुआ और शुक्रवार को भी मुश्किल से 10 से 15 फीसदी ही कारोबार हो पाया।'

इसी तरह, भागीरथ प्लेस के कारोबारी और दिल्ली इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष भरत आहूजा ने कहा कि पुरानी दिल्ली के बाजारों में बड़ी संख्या में खरीदार मेट्रो से आते हैं, लेकिन पिछले दो दिनों से प्रदर्शन के कारण मेट्रो परिचालन पर असर होने से कारोबार थम गया है। आहूजा ने कहा कि नजदीकी लालकिला और जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन बंद होने और विरोध-प्रदर्शन के कारण भागीरथ प्लेस में दो दिन से कारोबार में 70 से 80 फीसदी कमी देखी जा रही है।

दिल्ली व्यापार महासंघ के अध्यक्ष व सदर बाजार के कारोबारी देवराज बवेजा ने कहा,'चांदनी चौक, भागीरथ, चावड़ी बाजार और जामा मस्जिद के आस पास के बाजारों में ज्यादा परेशानी पेश आ रही है।

पुरानी दिल्ली के अन्य बाजारों में भी ग्राहकों की संख्या में 20 से 25 फीसदी की कमी देखी जा रही है। विरोध प्रदर्शनों के बीच बाहरी राज्यों के कारोबारी भी दिल्ली खरीदारी करने आने से परहेज कर रहे हैं।' दिल्ली के करोलबाग, पहाडगंज स्थित बजट होटलों के कारोबार पर भी विरोध-प्रदर्शन की मार पड़ी है।

ऑटो एक्सपो में चीन से आएगी रौनक

अरिंदम मजूमदार
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

ये कंपनियां होंगी शामिल

- मारुति सुजूकी
- महिंद्रा ऐंड महिंद्रा
- हुंडई
- टाटा मोटर्स
- एमजी मोटर्स
- फोक्सवैगन
- किया मोटर्स

करीब दर्जन भर प्रमुख भारतीय वाहन कंपनियां इस साल ऑटो एक्सपो में नहीं करेंगी शिरकत

देश की सबसे बड़ी वाहन प्रदर्शनी के आयोजकों की आस इस साल ऑटो एक्सपो में रौनक के लिए चीन की वाहन कंपनियों पर टिकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिग्गज भारतीय और वैश्विक वाहन विनिर्माताओं ने दुनिया के चौथे सबसे बड़े वाहन बाजार में नरमी के कारण एक्सपो में भाग नहीं लेने का निर्णय किया है।

चीन के तीन प्रमुख वाहन विनिर्माता इस साल 5 से 12 फरवरी को होने वाले ऑटो एक्सपो में अपने वाहनों को प्रदर्शित करेंगे। इनमें एमजी मोटर ब्रांड की मालिक साइक मोटर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्रेट वॉल मोटर्स और चंगन ऑटोमोबाइल शामिल हैं।

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सायम के अध्यक्ष राजन वढेरा ने कहा, 'चीन के तीन वाहन विनिर्माताओं ने इस साल एक्सपो में भाग लेने की पुष्टि की है।' हफ्ते भर चलने वाले ऑटो एक्सपो का आयोजन सायम ही करता है।

उद्योग के कार्याधिकारियों का कहना है कि चीनी कंपनियां अपने घरेलू बाजार में बिक्री में नरमी का सामना कर रही हैं और भारत को अवसर के रूप में देख रही हैं। हालांकि भारत में कारों की बिक्री में नरमी का रुख बना हुआ है लेकिन 2 एलएमसी ऑटोमोटिव कंसल्टेंसी के अनुसार भारत 2026 तक चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा बाजार बन सकता है।

वैश्विक दिग्गजों बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, ऑडी और जेएलआर इस बार ये भारत में ऑटो एक्सपो में शामिल नहीं होंगी। देश की प्रमुख दोपहिया विनिर्माता हीरो मोटोकॉर्प, होंडा मोटरसाइकिल्स ऐंड स्कूटर्स के साथ ही कार विनिर्माताओं में होंडा कार्स इंडिया, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर, फोर्ड, निसान और अशोक लीलैंड भी बार एक्सपो में शिरकत नहीं करेंगी। हीरो मोटोकॉर्प के प्रवक्ता ने कहा, 'बाजार की अगुआ होने के नाते हीरो मोटोकॉर्प हमेशा से ही एक्सपो की प्रमुख भागीदार रही है। एक्सपो में भागीदारी के लिए महीनों की तैयारी करनी होती है और काफी संसाधन लगते हैं। अपनी प्राथमिकता का ध्यान रखते हुए हमने आगामी एक्सपो में शामिल नहीं होने का निर्णय किया है।'

वढेरा ने कहा, 'जब आपको नुकसान हो रहा हो और उत्पादन घटाने को मजबूर होना पड़ रहा है, ऐसे में हमें आत्मविश्लेषण करना चाहिए और प्रचार और मार्केटिंग अभियानों पर हमें ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने चाहिए।'

घरेलू वाहन उद्योग की नरमी का व्यापक असर द्विवार्षिक ऑटो एक्सपो पर पड़ेगा। कंपनियां भागीदारी नहीं करने के पीछे ऊंची लागत, आयोजन स्थल के दूर होने और खराब प्रबंधन जैसे बाहरी कारणों का तर्क दे रही हैं। कुछ कंपनियों का कहना है कि इसमें मुख्य रूप से कारों और एसयूवी पर जोर रहता है जिससे बाइक, ट्रक और बस विनिर्माताओं के लिए काफी सीमित गुंजाइश रहती है।

5जी स्पेक्ट्रम नीलामी को मिली मंजूरी

पृष्ठ 1 का शेष...

भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और रिलांयस जियो कई बार कह चुकी हैं कि नियामक द्वारा निर्धारित आरक्षित कीमत काफी ज्यादा है और क्षेत्र की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कंपनियां 5जी स्पेक्ट्रम नीलामी से दूर रह सकती हैं।एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ने दूरसंचार क्षेत्र में वित्तीय दबाव को उजागर किया है क्योंकि दोनों कंपनियों को समायोजित राजस्व मद में भारी-भरकम रकम अदा करना है। दूरसंचार क्षेत्र पर करीब 4 लाख करोड़ रुपये का कर्ज है।चीन की कंपनी हुआवेई को 5जी का परीक्षण करने की मंजूरी के बारे में पूछे जाने पर प्रकाश ने कहा, 'इस बारे में अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है और जल्द ही राष्ट्र के हित में इस बारे में निर्णय लिया जाएगा।' इस बीच, डीसीसी ने कोच्चि और लक्षद्वीप के बीच समुद्री फाइबर केबल संपर्क को भी मंजूरी दे दी।

संक्षेप में

टाटा केमिकल्स ने एंडोवर समूह से खरीदी हिस्सेदारी

टाटा केमिकल्स ने टाटा केमिकल्स (सोडा ऐश) पार्टनर्स होल्डिंग्स की शेष 25 फीसदी हिस्सेदारी का अधिग्रहण कर लिया है। कंपनी ने यह हिस्सेदारी एंडोवर समूह से 19.5 करोड़ डॉलर यानी करीब 1,387.2 करोड़ रुपये में खरीदी है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस अधिग्रहण से टाटा केमिकल्स (सोडा एश) पार्टनर्स होल्डिंग्स में उसकी हिस्सेदारी बढ़कर शत फीसदी हो गई है। *भाषा*

अंकित गुप्ता ओयो के सीओओ नियुक्त

ओयो होटल्स ऐंड होम्स ने ने अंकित गुप्ता को भारत व दक्षिण एशिया के लिए को-लिविंग, रेंटल होम्स एवं स्वचालित होटल कारोबार का मुख्य परिचालन अधिकारी एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि गुप्ता को ओयो भारत एवं दक्षिण एशिया का फ्रंटियर बिजनेस का सीओओ एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। *भाषा*

ओएनजीसी को लौटाएंगी क्षेत्र

शेल, रिलायंस शनिवार को उसे सौपेंगी पन्ना-मुक्ता तेल एवं गैस क्षेत्र

शाइन जैकब
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

पन्ना-मुक्ता तेल एवं गैस क्षेत्र का 25 वर्षों तक परिचालन करने के बाद शेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज (आरआईएल) ने उसे सरकारी कंपनी ओएनजीसी को लौटाने का निर्णय लिया है। दोनों कंपनियों ने एक बयान में इसकी जानकारी दी है। इस तेल एवं गैस क्षेत्र का 25वां साल इस सप्ताह पूरा होने वाला है। इसके लिए 1994 में लाइसेंस दिया गया था।

पन्ना, मुक्ता और ताप्ती संयुक्त उद्यम में आरआईएल की 30 फीसदी और शेल की सहायक इकाई बीजी एक्सप्लोरेशन ऐंड प्रोडक्शन इंडिया लिमिटेड (बीजीईपीआईएल) के जरिये 30 फीसदी हिस्सेदारी है। शेष 40 फीसदी हिस्सेदारी सरकार द्वारा नामित ओएनजीसी के पास है।

आरआईएल और शेल ने आज जारी एक बयान में कहा, 'पन्ना-मुक्ता एवं ताप्ती (पीएमटी) संयुक्त उद्यम के साझेदार पन्ना-मुक्ता तेल एवं गैस क्षेत्र भारत सरकार की नामित कंपनी ओएनजीसी को 21 दिसंबर 2019 को सौंप देंगे।' ताप्ती क्षेत्र से उत्पादन 2016 के आरंभ में ही बंद हो गया था जबकि अन्य क्षेत्रों से उत्पादन में भी लगातार गिरावट आ रही थी।

फिलहाल पन्ना-मुक्ता तेल एवं गैस क्षेत्र में रोजाना करीब 10 हजार बैरल कच्चा तेल और 14 करोड़ स्टैंडर्ड घन फुट प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है। इस क्षेत्र ने अब तक 21.1 करोड़ बैरल कच्चा तेल और 1,250 अरब क्यूबिक फुट प्राकृतिक गैस का उत्पादन किया है।

पन्ना-मुक्ता एवं ताप्ती क्षेत्रों के लिए सरकार के साथ उत्पादन साझेदारी अनुबंध (पीएससी) पर 1994 में हस्ताक्षर किए गए थे और उसका परिचालन पीएमटी संयुक्त उद्यम के जरिये किया जा रहा था। अनुबंध की समय-सीमा 21 दिसंबर को खत्म हो रही है। पन्ना-मुक्ता क्षेत्र को लौटाए जाने के बावजूद ताप्ती क्षेत्र को बंद करने की गतिविधियां एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियां बीजीईपीआईएल द्वारा जारी रहेंगी।

बीजीईपीआईएल के प्रबंध निदेशक अरुण त्रिविक्रम ने कहा, 'पीएमटी संयुक्त उद्यम भारत की सबसे बड़ी राष्ट्रीय तेल कंपनी ओएनजीसी, भारत की सबसे बड़ी निजी कंपनी आरआईएल और अंतरराष्ट्रीय तेल कंपनी शेल के बीच सफल साझेदारी का एक जबरदस्त उदाहरण है। शेल को इस यात्रा में भागीदार होने से गर्व है और वह रिलायंस, ओएनजीसी और भारत सरकार के साथ इस साझेदारी से खुद को खास मान रही है। अनुबंध की समय-सीमा खत्म होने पर ओएनजीसी को ये क्षेत्र सुरक्षित लौटाने के लिए हमारी टीम ने लगातार काम कर रही है।'

आरआईएल के अध्यक्ष (उत्खनन एवं उत्पादन) बीजी गांगुली ने कहा, 'अपने चरम पर पन्ना-मुक्ता ताप्ती ने भारत के तेल उत्पादन में करीब 6 फीसदी का योगदान किया और 2007-08 में भारत के गैर उत्पादन में उसका योगदान करीब 7 फीसदी रहा। रिलायंस इस सफर का हिस्सा रही है और भारत के तेल एवं गैस क्षेत्र के विकास में योगदान किया है।'

पन्ना-मुक्ता एवं ताप्ती क्षेत्र

पन्ना-मुक्ता उत्पादन (1994 से)

- कच्चा तेलः 21.1 करोड़ बैरल
- प्राकृतिक गैसः 1.25 लाख करोड़ घन फुट

उत्पादन 2019 में

- कच्चा तेलः 10,000 बैरल प्रति दिन
- प्राकृतिक गैसः 14 करोड़ घन फुट रोजाना

टाटा के खिलाफ आदेश से निवेशक बेपरवाह

कृष्णकांत और देव चटर्जी
मुंबई, 20 दिसंबर

- टाटा संस के खिलाफ एनसीएलएटी के फैसले के बाद समूह के प्रमुख शेयरों ने दर्ज की बढ़त, छोटे शेयरों में रही कमजोरी

टाटा संस के चेयरमैन पद से साइरस मिस्त्री को हटाए जाने के मामले में नैशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) का फैसला कंपनी के खिलाफ रहने को इक्विटी निवेशकों ने अधिक तवज्जो नहीं दिया है। यही कारण है कि टाटा समूह के अधिकतर प्रमुख शेयरों ने पिछले तीन दिनों में मामूली गिरावट के बाद बढ़त दर्ज की है। एनसीएलएटी के फैसले से समूह के शीर्ष नेतृत्व के लिए पैदा हुई अनिश्चितता के बावजूद टाटा समूह के अधिकतर शेयरों में कोई उल्लेखनीय गिरावट नहीं दिखी।

एनसीएलएटी ने साइरस मिस्त्री को टाटा संस के चेयरमैन पद पर बहाल किया है और समूह के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन की नियुक्ति पर सवाल उठाया है। हालांकि समूह आगामी सप्ताहों में इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ स्थगनादेश हासिल सकता है। विश्लेषकों का कहना है कि सर्वोच्च न्यायालय से स्थगनादेश मिलने के बावजूद चंद्रशेखरन टाटा संस अथवा समूह की कंपनियों में शीर्ष स्तर पर नियुक्ति संबंधी बड़े फैसले नहीं कर सकेंगे। बाजार विशेषज्ञों का कहना है कि इससे समूह की उन प्रमुख कंपनियों के लिए निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होगी जिसके बोर्ड की अध्यक्षता टाटा संस के चेयरमैन करते हैं।

प्रॉक्सी एडवाइजरी फर्म इनगवर्न के संस्थापक एवं प्रबंध निदेशक श्रीराम सुब्रमण्यन ने कहा, 'इससे लघु अवधि में निश्चित तौर पर अनिश्चितता आएगी क्योंकि एनसीएलटी के फैसले में टाटा संस के मौजूदा चेयरमैन की नियुक्ति को अवैध करार दिया गया है। इस मामले को सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचने से टाटा समूह की कंपनियों की परेशानी बढ़ेगी।' लेकिन निवेशकों ने इसे अधिक तवज्जो नहीं दिया है। टीसीएस और टाइटन कंपनी के शेयरों में बुधवार के बाद बढ़त दर्ज की गई। समूह के कुल बाजार पूंजीकरण में इन दो कंपनियों का योगदान करीब 80 फीसदी है।

लेंसकार्ट का मूल्यांकन 1.5 अरब डॉलर पार

आईवियर स्टार्टअप लेंसकार्ट मासायोसी सोन के नेतृत्व वाले सॉफ्टबैंक के नेतृत्व में निवेशकों से जुटा रही 1,645 करोड़ रुपये जुटा रही है। लेंसकार्ट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने 12 दिसंबर 2019 को एक प्रस्ताव पारित कर जी शृंखला के निवेश के तहत एसवीएफ 2 (केमैन आइलैंड्स) लाइटबल्ब को करीब 2.29 करोड़ अनिवार्य परिवर्तनीय तरजीही शेयर जारी करने की मंजूरी दी थी। केमैन आइलैंड्स की यह कंपनी सॉफ्टबैंक विजन फंड (एसवीएफ) का निवेश इकाई है। बिजनेस सिग्नल्स प्लेटफॉर्म पेपर डॉट वीसी के अनुसार कंपनी ने नियामकीय खुलासे में यह जानकारी दी है।

पेपर डॉट वीसी के एक विश्लेषक जयराज पाटिल ने कहा, 'इस सौदे के तहत एसवीएफ 714 रुपये प्रति शेयर (अंकित मूल्य से 365 गुना अधिक) मूल्य पर 1,645 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है। हमारा मानना है कि इससे कंपनी का मूल्यांकन 1.5 अरब डॉलर के पार पहुंच जाएगा।' *बीएस*

मंदी से प्रभावित नहीं होगा वीईसीवी का खर्च

टीई नरसिम्हन
चेन्नई, 20 दिसंबर

वाहन बाजार में मंदी को देखते हुए वाणिज्यिक वाहन बनाने वाली तमाम कंपनियां अपने पूंजीगत खर्च में कटौती और निवेश घटाने की योजना बना रही हैं। लेकिन वीई कमर्शियल व्हीकल्स (वीईसीवी) इस वित्त वर्ष के दौरान भोपाल में एक नए संयंत्र और बीएस6 वाहन तैयार करने पर 650 से 700 करोड़ रुपये निवेश करने की योजना बना रही है। वीईसीवी वॉल्वो ग्रुप और आयशर मोटर्स का संयुक्त उद्यम है।

वीईसीवी के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी विनोद अग्रवाल ने बिजनेस स्टैंडर्ड से कहा कि मंदी का मौजूदा दौर तात्कालिक है और मध्यम एवं लंबी अवधि में परिदृश्य अच्छा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी कंपनी भविष्य के लिए तैयारी कर रही है क्योंकि वह लंबी अवधि की खिलाड़ी है।

कंपनी के भोपाल संयंत्र की क्षमता सालाना करीब 40,000 वाहनों का होगा जहां उत्पादन अगले साल से शुरू होने की उम्मीद है। पीथमपुर में कंपनी का एक संयंत्र पहले से ही मौजूद है जिसकी क्षमता करीब 90,000 वाहनों की है। इस विस्तार के साथ ही भारत मेकं कंपनी की कुल सालाना उत्पादन क्षमता बढ़कर 1.30 लाख वाहनों की हो जाएगी।

इन संयंत्रों से घरेलू मांग को पूरा करने के अलावा निर्यात भी किया जाएगा। कंपनी की कुल बिक्री में निर्यात का योगदान फिलहाल 15 फीसदी है। हाल के वर्षों में वीईसीवी निर्यात बाजार में अपना दायरा बढ़ाया है। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि कुल बिक्री में निर्यात बाजार का योगदान आगे और बढ़ेगा क्योंकि वह अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और सार्क देशों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है।

- वॉल्वो आयशर मोटर्स का संयुक्त उद्यम भोपाल में नए संयंत्र के अलावा बीएस6 के लिए करेगा 650 से 700 करोड़ रुपये का निवेश
- कंपनी की कुल बिक्री में निर्यात बाजार का योगदान आगे और बढ़ेगा क्योंकि वह अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया और सार्क देशों में अपनी पैठ बढ़ाना चाहती है

अग्रवाल ने उम्मीद जताई कि घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि से पहले खरीदारी के कारण कुछ आकर्षण दिख रहा है खासकर उन ग्राहकों के बीच जो अपना वाहन बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उद्योग के स्तर पर बीएस6 उत्सर्जन मानदंड वाले ट्रक की कीमत बीएस4 उत्सर्जन मानदंड वाले ट्रकों के मुकाबले 8 से 15 फीसदी अधिक है।

अग्रवाल ने दावा किया कि बीएस6 के मोर्चे पर वीईसीवी के वाहन अपेक्षाकृत सस्ते होंगे क्योंकि कंपनी वैश्विक स्तर पर वॉल्वो को एक लाख से अधिक यूरो6 इंजन की आपूर्ति पहले ही कर चुकी है। इसलिए कंपनी को बीएस6 तकनीक की भलीभांति जानकारी है।

वीईसीवी ने उम्मीद जताई है कि एमऐंडएचसीवी श्रेणी में उसकी बाजार हिस्सेदारी बीएस6 दौर में बेहतर होगी।

उद्योग के बारे में बताते हुए अग्रवाल ने कहा कि मंदी को हवा देने वाले कारकों में कमजोर आर्थिक वृद्धि और बुनियादी ढांचे पर कम खर्च है। इससे इस्पात एवं सीमेंट जैसे प्रमुख जिंस की आवाजाही प्रभावित हुई है। इसके अलावा एनबीएफसी क्षेत्र में दबाव के कारण वाहनों की बिक्री प्रभावित हुई है जिसे सरकार दूर करने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में बैंकों का पुनर्पूंजीकरण किया जा रहा है।

अग्रवाल ने कहा कि सरकार अर्थव्यवस्था और धारणा में सुधार के लिए भी कदम बढ़ा रही है। इसी क्रम में बुनियादी ढांचे पर खर्च को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कहा, 'इन सब कारकों के मद्देनजर हमें लगता है कि सितंबर से अक्टूबर 2020 से सुधार दिखने लगेगा।'

एम्बेसी ग्रुपः ऑफिस रीट में बढ़ाएगी परिसंपत्ति

देवाशिष महापात्र
बेंगलूरु, 20 दिसंबर

एम्बेसी ग्रुप आगामी तिमाहियों में और अधिक परिसंपत्तियों को अपने ऑफिस पार्क रीट (रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट) के दायरे में लाने की योजना बना रहा है। यह समूह 3,000 करोड़ रुपये जुटाने के बाद भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर अपने रीट को सूचीबद्ध कराने वाली पहली कंपनी है। बेंगलूरु की रियल एस्टेट कंपनी ने इस साल के आरंभ में 9.4 फीसदी प्रतिफल के साथ जून 2022 में परिपक्वता वाले गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के जरिये रकम जुटाई थी। एम्बेसी के अलावा ब्लैकस्टोन ग्रुप एलपी इस रीट का अन्य प्रायोजक है।

एम्बेसी ग्रुप के मुख्य परिचालन अधिकारी आदित्य विरवानी ने कहा, 'हमारा रीट काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है और हम उसमें कुछ अन्य परिसंपत्ति भी डाल रहे हैं।' उन्होंने कहा, 'अनुमानित नकदी प्रवाह के कारण रीट मॉडल की ओर हमारा कहीं अधिक झुकाव है। इसलिए इस परिसंपत्ति वर्ग में निवेशक कहीं अधिक सहज महसूस करते हैं।'

फिलहाल एम्बेसी ऑफिस पार्क्स रीट के पास 2.5 करोड़ वर्ग फुट तैयार परिसंपत्तियां हैं। जबकि बेंगलूरु और मुंबई जैसे प्रमुख शहरों में 80 लाख वर्ग फुट की अन्य परिसंपत्तियां उसके पास आने वाली हैं। अपना ऑफिस स्पेस रीट शुरू करने के बाद एम्बेसी ग्रुप को वेयरहाउस क्षेत्र में भी इसी तरह की संभावनाएं दिख रही हैं।

एम्बेसी ग्रुप के सीओओ ने कहा, 'वेयरहाउसिंग को भी हम एक रीट के दायरे में लाएंगे। किराये से अनुमानित आय वाली इसी तरह की परिसंपत्तियों का एक उल्लेखनीय पोर्टफोलियो होने के बाद हम ऐसा करेंगे।'

एम्बेसी ग्रुप के प्रवर्तक एवं प्रबंध निदेशक जीतू विरवानी के छोटे बेटे आदित्य विरवानी ने इसी साल अक्टूबर में सीओओ का पदभार संभालने के बाद नई परिसंपत्ति वर्ग में दांव लगाना भी शुरू कर दिया है। विरवानी ने कहा, 'फेज 1 एक्सपीरिएंस के साथ साझेदारी में हम संयुक्त रूप से भारत के पहले बहुउद्देश्य वेन्यू का विकास कर रहे हैं जिसका इस्तेमाल बेंगलूरु इंटरनैशनल एयरपोर्ट पर कंसर्ट एवं एक्पो आदि के लिए किया जा सकता है।'

कंपनी के अनुसार, लाइव कार्यक्रम एवं मनोरंजन उद्योग का राजस्व वित्त वर्ष 2021 तक 10,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है। ऐसे में इस प्रकार के फैसिलिटी से एम्बेसी ग्रुप को अपने राजस्व स्रोत को विविध करने में मदद मिलेगी।

विरवानी ने कहा, 'हालांकि इस नई फैसिलिटी के लिए निवेश की रकम महज करीब 100 करोड़ रुपये होगी लेकिन यह एक अन्य परिसंपत्ति श्रेणी है जहां एम्बेसी दांव लगा रही है।' इस नई फैसिलिटी में कंसर्ट अथवा बड़े आयोजन के दौरान करीब 9,000 लोगों बैठ सकते हैं और इसे पूरा होने में करीब 18 महीने लगेंगे। उन्होंने कहा, 'यदि यह परियोजना सफल रहती है तो हम उन दूसरे हवाई अड्डों पर गौर करेंगे जो इस प्रकार की फैसिलिटी स्थापित करना चाहते हैं।'

झाबुआ के लिए बोली लगाएगी एनटीपीसी!

श्रेया जय
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

भारत की सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली बिजली उत्पादक कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड पहली बार ऋणशोधन अक्षमता एवं दिवालिया संहिता (आईबीसी) के तहत दबावग्रस्त किसी परिसंपत्ति के लिए बोली लगा सकती है। एनटीपीसी अवंता पावर की झाबुआ थर्मल पावर परियोजना (1,200 मेगावाट) के लिए बोली लगाएगी जिसे ऐक्सिस बैंक के नेतृत्व वाले ऋणदाता कंसोर्टियम द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) में प्रस्तुत किया गया है।

कंपनी के सूत्रों ने कहा कि बैंक धन देने के लिए तैयार हैं। एनटीपीसी केवल आईबीसी के तहत आयोजित बोली में ही भाग लेगी। अधिकारियों ने कहा कि कंपनी बोली लगाने के लिए परिसंपत्तियों के चयन की खातिर सख्त मानदंडों का पालन करेगी।

पहचान उजागर न करने का आग्रह करते हुए कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हम उन परियोजनाओं पर विचार कर रहे हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोयला आपूर्ति स्रोत, किसी प्रख्यात ठेकेदार द्वारा निर्मित मजबूत बुनियादी ढांचा, भूमि और संबंधित मंजूरियां प्राप्त हों तथा वह सक्रिय हो या परिचालन के लिए तैयार स्थिति में हों। वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परियोजना के संबंध में बिजली खरीद अनुबंध (पीपीए) का अभाव होना कोई बाधा नहीं है क्योंकि एनटीपीसी बिजली बिक्री की सुविधा दे देगी।

उन्होंने कहा कि एनटीपीसी या तो राज्यों के साथ लंबी अवधि (25 वर्ष) के पीपीए पर हस्ताक्षर करेगी या फिर केंद्रीय एजेंसियों के जरिये मध्य अवधि के अनुबंधों के माध्यम से बिजली की बिक्री करेगी। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होता है तो हम इन इकाइयों का इस्तेमाल व्यापारिक या हाजिर बाजार में बिजली बेचने के लिए भी कर सकते हैं।

- 4,800 करोड़ रुपये की है यह परियोजना और इस पर है 3,488 करोड़ रुपये का कर्ज
- वर्ष 2016 में शुरू किया गया था झाबुआ प्लांट
- नियोजित लगभग 1,200 मेगावाट में से 600 मेगावाट वाली केवल एक इकाई की ही हो पाई थी शुरुआत
- अपने शीर्ष क्षमता स्तर से नीचे चलता रहा है यह संयंत्र
- इससे लाभ पाने वाले राज्यों मध्य प्रदेश और केरल की मांग रही थी कमजोर

एनटीपीसी ने पहले अपने मानदंडों से मेल खाने वाली 10,000 मेगावाट क्षमता का चयन किया था। इसने दबावग्रस्त परिसंपत्ति खरीदने के लिए निविदा भी जारी की थी और चार कंपनियों की तरफ से रुचि भी दिखाई गई थी। सूत्रों के अनुसार परियोजना मूल्यांकन से संबंधित मसलों की वजह से कंपनी इसे अंतिम रूप नहीं दे पाई।

झाबुआ उन 40 दबावग्रस्त थर्मल पावर यूनिटों की सूची में शामिल है जिन्हें गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) माना जाता है। झाबुआ पावर प्लांट बेचने के लिए पहले किए गए प्रयासों का कोई परिणाम नहीं निकल पाया था। गोयल एमजी गैसेस के साथ भी इसका बिक्री सौदा परवान नहीं चढ़ पाया था।

वर्ष 2016 में शुरू किया जाने वाला झाबुआ पावर प्लांट मध्य प्रदेश में स्थित है। नियोजित 1,200 मेगावाट में से 600 मेगावाट की केवल एक इकाई की ही शुरुआत की गई थी। इस संयंत्र के लिए कोयले की आपूर्ति महानदी कोलफील्ड्स और साउथ-ईस्टर्न कोलफील्ड्स से की गई थी। यह संयंत्र शीर्ष क्षमता स्तर से नीचे चलता रहा है। पहले ऐसा इसलिए था क्योंकि इससे लाभ पाने वाले राज्यों मध्य प्रदेश और केरल की मांग कमजोर थी। बाद में मूल कंपनी ने आवश्यक कार्यशील पूंजी नहीं दी और संयंत्र को कोयला आपूर्ति के संकट का भी सामना करना पड़ा। यह परियोजना 4,800 करोड़ रुपये की है और इस पर 3,488 करोड़ रुपये का कर्ज है।

एमएफ जैसे निकासी विकल्प चाहता है पीएफआरडीए

नियामकीय संस्था ने एम्फी की तर्ज पर एक उद्योग संगठन के गठन की भी योजना बनाई है

जश कृपलानी
मुंबई, 20 दिसंबर

पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) का कहना है कि राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) में सिस्टमैटिक विदड्रॉल प्लान्स (एसडब्ल्यूपी) की अनुमति दी जाए जिससे कि ग्राहक एन्युटी उत्पादों के बजाय ज्यादा सक्षम विकल्प चुन सकें।

पीएफआरडीए के पूर्णकालिक सदस्य (वित्त) सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने उन बदलावों के बारे में जानकारी दी जिनके लिए नियामक ने सरकार से अनुरोध किया है।

सूत्रों के अनुसार, पीएफआरडीए आगामी बजट में सरकार द्वारा इनमें से कुछ बदलावों पर अमल किए जाने की उम्मीद कर रहा है।

एनपीएस में, प्राप्त पेंशन परिसंपत्तियों का 40 प्रतिशत हिस्सा एन्युटी योजना में इस्तेमाल किए जाने की जरूरत होगी, जबकि 60 प्रतिशत को ग्राहक द्वारा लिया जा सकेगा। पीएफआरडीए के अधिकारियों का कहना है कि कम प्रतिफल और एन्युटी पर कराधान के साथ निवेशक एसडब्ल्यूपी विकल्प के साथ बेहतर स्थिति में होंगे।

परिपक्वता के समय एनपीएस से प्राप्त होने वाली कुल रकम का 60 प्रतिशत हिस्सा कर-मुक्त है, वहीं ग्राहक को प्राप्त होने की स्थिति में एन्युटी पर कर लागू है। पीएफआरडीए ने सुझाव दिया है कि सिर्फ अर्जित ब्याज आय पर ही कर लगना चाहिए, न कि पूरी एन्युटी पर। एनपीएस की कुल प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां (एयूएम) 14 दिसंबर, 2019 तक 3.92 लाख करोड़ रुपये थीं।

अपने बजट प्रस्तावों के तौर पर, पीएफआरडीए ने सरकार से धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर छूट की सीमा 50,000 रुपये सालाना से बढ़ाकर 100,000 रुपये किए जाने को भी कहा है।

पीएफआरडीए चाहता है कि पेंशन योजनाओं की निगरानी के लिए अलग नियामकीय संस्थाओं के बजाय सभी पेंशन-आधारित उत्पादों को उसके दायरे में लाया जाना चाहिए। मौजूदा समय में, पेंशन योजनाओं में कुल प्रबंधन अधीन परिसंपत्तियां लगभग 25 लाख करोड़ रुपये पर हैं।

पीएफआरडीए ने यह भी सुझाव दिया है कि एनपीएस ट्रस्ट पीएफआरडीए से अलग होना चाहिए। बंद्योपाध्याय ने कहा, 'ट्रस्ट का निर्माता और समाधानकर्ता होने से हितों का टकराव पैदा हो सकता है।'

इसके अलावा, नियामक ने टियर-2 वोलंटरी एनपीएस खातों के लिए 80सी के तहत कर छूट दिए जाने का भी प्रस्ताव रखा है। मौजूदा समय में, यह कर छूट केंद्र सरकार के कर्मचारियों द्वारा ही ली जा सकती है। पीएफआरडीए ने अन्य कर्मचारियों को भी यह छूट दिए जाने की मांग की है।

पीएफआरडीए ने एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड्स इन इंडिया (एम्फी) जैसा उद्योग संगठन तैयार करने की भी योजना बनाई है। बंद्योपाध्याय ने कहा कि म्युचुअल फंड योजनाओं की पहुंच बढ़ाने के लिए एम्फी द्वारा किए गए निवेशक जागरूकता कार्य से हम उत्साहित हैं।

सूत्रों का कहना है कि एनपीएस योजनाओं के संदर्भ में प्रबंधन शुल्क में सुधार लाने के लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं जिससे प्रबंधन शुल्क के संदर्भ में नया मानक स्थापित हो सकता है।

उद्योग के जानकारों का कहना है कि मौजूदा समय में, कम प्रबंधन शुल्क की वजह से अन्य कंपनियां इस दौड़ में शामिल होने से परहेज करती हैं।

पिछले 10 वर्षों के दौरान, इक्विटी एनपीएस योजनाओं ने 11 प्रतिशत का सालाना प्रतिफल दिया। कॉरपोरेट बॉन्ड योजनाओं ने 10.3 प्रतिशत, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों ने 9.5 प्रतिशत का प्रतिफल दिया।

वहीं उपर्युक्त योजनाओं के समावेश के साथ निवेश करने वाले सतर्क निवेशकों को पिछले 10 वर्षों में 10 प्रतिशत का प्रतिफल मिला।

पीएफआरडीए की मांग

- धारा 80सीसीडी (1बी) के तहत कर छूट बढ़ाकर 100,000 रुपये की जाए
- केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला 80सी का लाभ दूसरे खाताधारकों को भी मिले
- सभी पेंशन योजनाएं एक नियामकीय संगठन के दायरे में लाई जाएं
- जागरूकता पैदा करने के लिए एम्फी की तर्ज पर एक संगठन बने
- आगामी बजट में सरकार से कई संबंधित बदलावों की उम्मीद है

एफआईआई को दो-तिहाई शेयरों में घाटा

जश कृपलानी
मुंबई, 20 दिसंबर

विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) के लिए यह वर्ष ज्यादा बढ़िया नहीं रहा। उन्हें कैलेंडर वर्ष 2019 के पहले 9 महीनों के दौरान निवेश से जुड़े दो-तिहाई शेयरों में कमजोर प्रतिफल का सामना करना पड़ा।

कैपिटालाइन से प्राप्त आंकड़े के विश्लेषण से पता चलता है कि एफआईआई द्वारा जिन 423 सूचीबद्ध कंपनियों में निवेश किया गया, उनमें से 278 ने इस साल अब तक (वाईटीडी) कमजोर प्रतिफल दिया है।

बाजार विश्लेषकों का कहना है कि एफआईआई ने अपना निवेश कर्ज और चक्रीयता से जुड़ी समस्याओं का सामना कर रही कंपनियों में किया। एक फंड प्रबंधक ने कहा, 'एफआईआई ने इन शेयरों पर यह सोचकर दांव लगाया कि आर्थिक सुधार के साथ इनमें अच्छी तेजी आएगी। लेकिन यह निवेश रणनीति मौजूदा बाजार परिदृश्य में कारगर साबित नहीं हुई है।'

- मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट्स में एफआईआई के लिए 66 शेयरों में कारोबार इस साल अब तक कमजोर प्रतिफल वाला रहा है

एचडीएफसी सिक्योरिटीज के प्रमुख (रिटेल रिसर्च) दीपक जसानी ने कहा, 'मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयरों में ज्यादा निवेश करने वाले एफआईआई को प्रमुख सूचकांकों में अस्थिरता की वजह से नुकसान का सामना करना पड़ा।' आंकड़ों से पता चलता है कि मिड-कैप और स्मॉल-कैप सेगमेंट्स में एफआईआई के लिए 66 शेयरों में कारोबार इस साल अब तक कमजोर प्रतिफल वाला रहा है।

ग्रेफाइट निर्माता एचईजी (69 प्रतिशत की गिरावट) और ग्रेफाइट इंडिया (59 प्रतिशत की गिरावट) इस सूची में शीर्ष पर हैं, जिनमें एफआईआई ने चालू वर्ष 2019 के पहले 9 मीनों में 148 आधार अंक और 238 आधार अंक तक हिस्सेदारी बढ़ाई।

पीएनबी हाउसिंग ऐसा अन्य शेयर रहा जिसमें एफआईआई निवेश 353 आधार अंक बढ़ा, जबकि शेयर कीमत में 53 प्रतिशत तक की कमी दर्ज की गई।कई प्रमुख सूचकांक इस तेजी में भागीदार बनने में विफल रहे हैं। जहां सेंसेक्स और निफ्टी ने 15 और 12 प्रतिशत का प्रतिफल दिया है, वहीं मिड-कैप और स्मॉल-कैप सूचकांकों में इस साल अब तक 4 प्रतिशत और 8.9 प्रतिशत की कमजोरी आई है। फंड प्रबंधक ने कहा, 'कमजोर मूल्यांकन की वजह से इनमें से कुछ मिड-कैप और स्मॉल-कैप शेयर वर्ष के शुरू में आकर्षक दिख रहे थे। लेकिन इनमें से कुछ शेयरों में निवेश का उनका फैसला गलत साबित हुआ, क्योंकि इन कंपनियों के बुनियादी आधार में और ज्यादा कमजोरी देखने को मिली।' एफआईआई लार्ज-कैप श्रेणी में भी कई शेयरों में चुनौतीपूर्ण निवेश से जूझना पड़ा है। एस्सेल समूह कंपनी जी एंटरटेनमेंट का शेयर इस साल अब तक 41 प्रतिशत टूट चुका है।

आरबीआई के ओएमओ वादे से दीर्घावधि बॉन्ड प्रतिफल लुढ़का

अनूप रॉय
मुंबई, 20 दिसंबर

10 वर्षीय बॉन्ड प्रतिफल में 15 आधार अंक की जबकि 14 वर्षीय सेगमेंट में 20 आधार अंक की गिरावट आई है। बॉन्ड बाजार के डीलरों का मानना है कि इससे सरकार को सस्ती लागत पर पूंजी जुटाने में मदद मिलेगी, बशर्ते कि केंद्र सरकार बाजार में इस तरह के प्रयास बरकरार रखे। आरबीआई ने कहा है कि वह 10 वर्षीय बॉन्ड खरीदेगा और चार अल्पावधि बॉन्डों की बिक्री करेगा। इसके बाद 10 वर्षीय बॉन्ड का प्रतिफल 6.604 प्रतिशत पर बंद हुआ। एक वर्षीय बॉन्ड पर प्रतिफल 5 आधार अंक चढ़ा। बॉन्ड डीलरों का कहना है कि यदि केंद्रीय बैंक ऐसा सिर्फ एक बार करती है तो प्रतिफल फिर से बढ़ सकता है। एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के प्रमुख (फिक्स्ड इनकम) बद्रीश कुल्हाली के अनुसार, एक दिन के और 10 वर्षीय बॉन्ड के बीच अंतर बढ़कर 160 आधार अंक हो गया, लेकिन दीर्घावधि औसत 80-100 आधार अंक रहा, जिस पर केंद्रीय बैंक ध्यान दे रहा है।

डॉ. रेड्डीज के लिए मजबूत है विकास परिदृश्य

उज्ज्वल जौहरी
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

घरेलू बाजार पर ध्यान केंद्रित करने की डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज (डीआरएल) की रणनीति मददगार साबित होती दिख रही है। इससे कंपनी को पिछली आठ तिमाहियों में से सात में घरेलू दवा बाजार में अच्छा प्रदर्शन करने में मदद मिली है। नवंबर में डीआरएल ने सालाना आधार पर 27 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, जो उसके प्रतिस्पर्धियों में सर्वाधिक और उद्योग वृद्धि (14.5 प्रतिशत) के मुकाबले दोगुनी थी। 15.4 प्रतिशत पर पिछले 12 महीने की औसत वृद्धि भी 9.8 प्रतिशत की फार्मा क्षेत्र की वृद्धि की तुलना में अधिक है।

जहां कंपनी का घरेलू प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है, वहीं उसने चीन समेत उभरते बाजारों में अपने प्रदर्शन में सुधार दर्ज किया है।

अमेरिका में, उसने अपनी रणनीति में बदलाव किया है और वह इंजेक्टीबल्स जैसे सीमित प्रतिस्पर्धा वाले उत्पादों पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं। कंपनी दीर्घावधि राजस्व बढ़ाने के लिए बायोसिमिलर और अन्य उत्पादों के निर्माण पर भी जोर दे रही है।

डीआरएल की स्वयं की पेशकश से पहले एक प्रतिस्पर्धी द्वारा नुवारिंग (97.6 करोड़ डॉलर के कॉन्ट्रासेप्टिव व्यवसाय) के जेनेरिक वर्सन की ताजा पेशकश सुर्खियां बन गई थी।

हालांकि इससे शेयर के लिए हल्का झटका जरूर लगा था, लेकिन हैटॉन्ग सिक्योरिटीज के अमेय चालके का कहना है कि यह आश्चर्यजनक नहीं था। विश्लेषकों का कहना है कि कंपनी वित्त वर्ष 2020 के अंत तक या वित्त वर्ष 2021 की पहली छमाही तक उत्पाद पेशकश की तैयारी कर रही थी, जिसका असर वित्त वर्ष 2021 के अनुमानों में दिखा। इसलिए, इससे आगामी वर्ष में ब्रोकरों के आय अनुमानों में बदलाव नहीं आया है। माना जा रहा था कि नुवारिंग व्यवसाय चार कंपनियों वाला बाजार होगा, और 50 प्रतिशत की कीमत गिरावट तथा 10 प्रतिशत की बाजार भागीदारी के साथ डीआरएल सालाना 5 करोड़ डॉलर की बिक्री हासिल करने में सक्षम होगी। इसके अलावा, उत्पाद से जुड़ी जटिलता इस तरह की है जिससे लगता है कि यह 4-5 कंपनियों वाला बाजार बना रहेगा।

तेजी से बढ़ रहे घरेलू बाजार और अमेरिका में नए उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार प्रमुख सकारात्मक कारक हैं

सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद ऐंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के विश्लेषकों ने संकेत दिया था कि नुवारिंग और कोपेक्सोन (ऑनकोलॉजी ड्रग) की जेनेरिक पेशकश में विलंब से जुड़ी चिंताओं के बावजूद डीआरएल के पास मजबूत उत्पाद प्रवाह बना हुआ है। इसमें क्यूबीसिन (एंटीबायोटिक), रेमोड्यूलिन (उच्च रक्तचाप), ट्रींडा (ऑनकोलॉजी), और सेंसिपर (थायरॉयड) के साथ साथ वित्त वर्ष 2021 में डेक्सिलेंट (एसिड रीफ्लक्स उपचार), कोपेक्सोन और कुवान (रक्त अनियमितता) के जेनेरिक्स शामिल हैं।

कंपनी को अमेरिकी बाजार में तेजी से मंजूरियां मिली हैं। इस महीने उसे रक्त संचरण ड्रग टैबलेट और सस्पेंशन की पेशकश के लिए मंजूरियां मिलीं और उसने एक इंजेक्टीबल दवा को पेश किया है। कंपनी ने उत्पादों के लिए आवेदन करने को लेकर भी अधिक आक्रामक रणनीति अपनाई है।

इन्फ्रा फंड के लिए 10 परियोजनाएं चिह्नित

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकारी बैंकों को आरबीआई के पास पैसा रखने के बजाय कर्ज देना चाहिए

अरूप रायचौधरी
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज कहा कि सरकारी बैंकों को रिजर्व बैंक के पास रिर्वस रीपो के रूप में ज्यादा पैसा रखने की बजाय ज्यादा कर्ज बांटने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि नकदी की किल्लत से सबसे अधिक जूझ रहीं गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों (एनबीएफसी) को नकदी मुहैया कराई गई है। दरअसल सरकार सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए कई कदम उठा रही है।

औद्योगिक निकाय एसोचैम की ओर आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीतारमण ने यह भी कहा कि एक बुनियादी ढांचा कोष के तहत कम से कम 10 परियोजनाओं की पहचान की गई है और उन्हें अग्रिम रकम मुहैया कराई जाएगी। उन्होंने कहा, 'मैंने अपने बजट भाषण में कहा था कि बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे। मैंने यह भी घोषणा की थी कि यह राशि अग्रिम दी जाएगी। आगामी वर्ष में कम से कम 10 नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी जाएगी ताकि उन्हें अग्रिम पैसा मिल जाए।'

बजट में सीतारमण की घोषणा के बाद केंद्र सरकार ने सितंबर में एक उच्च स्तरीय कार्यबल का गठन किया था, जिसे 2024-25 तक 100 करोड़ रुपये के निवेश के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को चिह्नित करने का काम सौंपा गया था।

सीतारमण ने उद्योग के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय कंपनियों को 'खुद पर संदेह' के मूड से बाहर आना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि बजट के बाद उठाए गए कदमों का जमीन पर असर दिखने लगा है। सीतारमण ने कहा कि भारत के वृहद आर्थिक संकेत मजबूत आधार पर टिके हैं। महंगाई को नियंत्रित रखा गया है, वृहद आर्थिक रुझान और एफडीआई की आवक मजबूत है और विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड ऊंचाई पर है।

उन्होंने कहा, 'यह सरकार नहीं चाहती कि कारोबार बंद हों। हम विधायी और प्रशासनिक बदलावों के जरिये उन्हें उबारना चाहते हैं...हम आपके साथ हैं। मैं चाहती हूं कि आप अपने दिमाग से खुद पर संदेह को पूरी तरह से भगा दें।' सीतारमण ने कहा, 'बजट के बाद कई कदम उठाए गए हैं, जो उद्योग के लिए थे। संभवतया उनमें से कुछ ने जमीन पर सकारात्मक असर दिखाना शुरू कर दिया है।'

उन्होंने सरकार द्वारा बजट के बाद उठाए गए कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि नकदी की किल्लत दूर की गई है, सरकारी बैंकों एवं एनबीएफसी में पूंजी डाली गई है और पीएसयू के बोर्ड को पेशेवर बनाया गया है।

मंत्री ने कहा कि सरकार ने सितंबर में कॉरपोरेट कर की दर में कटौती की है। इससे भारत में बड़ी मात्रा में निवेश आने के आसार हैं। वित्त मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार कर संग्रह में पारदर्शिता और तकनीक का उपयोग लेकर आई है और करदाताओं का शोषण खत्म किया गया है। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत मौजूदी के बिना कर आकलन शुरू होने से कर शोषण गुजरे जमाने की बात होने जा रही है।

उन्होंने कहा, 'हम हर किसी को आश्वस्त करते हैं कि अगर आपको कर अधिकारियों से नोटिस मिलता है और यदि इस पर डीआईएन नवंबर नहीं है तो इसे कोई नोटिस मत मानिए... इसके बाद भी आपको नोटिस मिलता है तो इसका जवाब दें। इसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो यह बिना व्यक्तिगत मौजूदगी के कर आकलन होगा।'

वित्त मंत्री ने एसोचैम के कार्यक्रम में कहा-

- नकदी की किल्लत से सबसे अधिक जूझ रहीं एनबीएफसी को नकदी मुहैया कराई गई
- बजट भाषण में कहा था कि बुनियादी ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ रुपये दिए जाएंगे
- विधायी और प्रशासनिक बदलावों के जरिये उद्यमों को उबारने की बात कही

घाटे के बजाय वृद्धि पर दें पूरा ध्यान

बहुत से अर्थशास्त्रियों ने शुक्रवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और उनके अधिकारियों को सलाह दी कि वे कुछ समय राजकोषीय चिंताओं को भूलकर केवल आर्थिक वृद्धि पर ध्यान दें। बजट पूर्व बैठक में वित्त मंत्री को कहा गया कि भारतीय रिजर्व बैंक की मदद से गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को मौजूदा संकट से उबारा जाए। इस बैठक में मौजूद एक व्यक्ति ने कहा, 'लगभग सभी मौजूद अर्थशास्त्रियों ने कहा कि केंद्र को अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए खर्च बढ़ाने की जरूरत है। वृद्धि शीर्ष प्राथमिकता होनी चाहिए।' बैठक में मौजूद अर्थशास्त्रियों ने कहा कि मध्यम अवधि में तीन फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश करना बेकार है क्योंकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लागू होने के बाद यह लक्ष्य कभी हासिल नहीं हो पाया है। केंद्र को उम्मीद है कि वह 2020-21 में जीडीपी के 3 फीसदी राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल कर लेगा। वित्त वर्ष 2019-20 के लिए घाटे का लक्ष्य 3.3 फीसदी है। हालांकि कर राजस्व प्रभावित होने घाटा 3.8 फीसदी रह सकता है।

'राजकोषीय मजबूती पर टिकी रहे सरकार'

दिलाशा सेठ और इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

भारत को मध्यावधि में राजकोषीय मजबूती की योजना पर निश्चित तौर पर कायम रहना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की प्रमुख गीता गोपीनाथ ने आज यह बात उद्योग चैंबर फिक्की की 92वे वार्षिक सम्मेलन में बोलते हुए कही। उनका यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब यह बहस छिड़ी हुई है कि क्या सरकार को अर्थव्यवस्था को ऊपर उठाने के लिए सरकारी खर्च में इजाफा करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि आईएमएफ जनवरी में भारत की वृद्धि रुझान में सुधार करेगा क्योंकि उच्च आवृत्ति संकेतक दूसरी छमाही में वैसी तेजी नहीं दिखा रहे हैं जिसकी उम्मीद की जा रही थी।

गोपीनाथ ने कहा, 'भारत के लिए वृहत् स्थिरता बहुत महत्त्वपूर्ण है जिसका मतलब राजकोषीय मोर्चे पर स्थायित्व है। वित्तीय समेकन के लक्ष्य पर बने रहने का स्पष्ट नजरिया बहुत महत्त्वपूर्ण है जिसके लिए राजस्व बढ़ाने के साथ ही खर्च में कटौती करना भी जरूरी होगा।'

वस्तु एवं सेवा कर के तहत

गीता गोपीनाथ, प्रमुख, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष

मिलने वाले राजस्व में भारी गिरावट के बीच कई राज्यों ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को राजकोषीय घाटे का लक्ष्य सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 3.3 फीसदी से बढ़ाकर 4 फीसदी करने और राज्यों की एफआरबीएम सीमा को 3 फीसदी से बढ़ा कर 4 फीसदी करने के लिए कहा था।

हालांकि गोपीनाथ ने कहा, 'जब हम वित्तीय समेकन की बात करते हैं तब हम उसे मध्यावधि लक्ष्य के तौर पर लेते हैं जिसे एक समयावधि में किया जाना चाहिए न कि इसे रातोंरात कर देने की जरूरत है।' उन्होंने कहा कि भारत का संयुक्त घाटा (केंद्र और राज्यों का घाटा मिलाकर) जी20 के अन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक है। उन्होंने कहा, 'इसलिए यह दोपहर के मुफ्त भोजन की तरह नहीं है और इसे बहुत सावधानीपूर्वक प्रबंधित किया जाना चाहिए।' जीएसटी पर आईएमएफ प्रमुख ने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था को औपचारिकता प्रदान करने के लिए सुधार किया जाना जरूरी था लेकिन जहां तक नियमन और कर की दरों का सवाल है इस पर निश्चितता और स्पष्टता की जरूरत थी। 1 जुलाई, 2017 से जीएसटी को लागू किए जाने के बाद से 400 से अधिक सामानों पर और करीब 80 फीसदी सेवाओं पर जीएसटी की दरों में बदलाव किया गया है। सरकार जीएसटी राजस्व में आई कमी की पूर्ति के लिए फिर से कुछ स्लैबों में बदलाव करने की योजना बना रही है। भारत की आर्थिक वृद्धि के परिदृश्य में संशोधन पर गोपीनाथ ने कहा कि कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों से तीसरी और चौथी तिमाही में जैसी वृद्धि की उम्मीद थी वह नजर नहीं आई है।

उन्होंने कहा, 'हम उम्मीद कर रहे थे कि वित्त वर्ष 2019-20 की पहली दो तिमाहियों में सुस्ती का परिदृश्य नजर आएगा और उसके बाद तीसरी और चौथी तिमाही में तेजी दिखाई पड़ेगी। कुछ उच्च आवृत्ति संकेतकों पर नजर डालने के बाद हमें उस तरह की तेजी नजर नहीं आ रही है जैसी की हमने उम्मीद की थी।

सुस्त पड़ेंगी बीओटी राजमार्ग परियोजनाएं

मेघा मनचंदा
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) की अधिक जोखिम वाली निर्माण-परिचालन-हस्तांतरण राजमार्ग परियोजनाओं की कुल सड़क निर्माण में हिस्सेदारी अगले तीन साल में घट सकती है क्योंकि वित्तीय संस्थान इन परियोजनाओं के लिए धन देने को लेकर चिंताएं जता रहे हैं। एनएचएआई के एक अधिकारी ने बिज़नेस स्टैंडर्ड को बताया, 'बीओटी परियोजनाओं की मांग नहीं है, इसलिए इनकी रफ्तार सुस्त रहेगी।' अधिकारी ने कहा कि बड़ी सड़क विनिर्माण कंपनियां भी बीओटी परियोजनाओं पर दांव लगाने की इच्छुक नहीं हैं। इसका मतलब है कि प्राधिकरण को बीओटी मॉडल को लेकर फिर से विचार करना होगा। क्रिसिल रिसर्च की निदेशक हेतल गांधी ने कहा, 'वित्त वर्ष 2018-19 में एनएचएआई द्वारा बीओटी मॉडल पर आवंटित परियोजनाएं शून्य रही। हमारा अनुमान है कि अगले तीन वर्षों के दौरान सरकार के प्रोत्साहनों से बीओटी परियोजनाओं के आवंटन में थोड़ी तेजी आएगी।'

'चालक रहित कारों को नहीं मिलेगी मंजूरी'

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने शुक्रवार को कहा कि वह देश में चालक रहित (ड्राइवरलेस) कारों को अनुमति नहीं देंगे। उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा, 'मुझसे कई बार बिना चालक वाली कारों के बारे में पूछा जाता है। तब मैं कहता हूं कि जब तक मैं परिवहन मंत्री हूं, तब तक आप भूल जाएं। मैं ड्राइवरलेस कार को भारत में नहीं आने दूंगा।'

देश में 22 लाख चालकों की कमी की बात कहते हुए गडकरी ने कहा कि देश में रोजगार में वृद्धि के साथ-साथ उद्योग में भी वृद्धि की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वाहन कबाड़ नीति अंतिम चरणों में है और 'यदि हम इसे लाते हैं तो हमारी लागत 100 प्रतिशत घट जाएगी क्योंकि कच्चा माल सस्ता हो जाएगा और भारत ई-वाहन, वाहन विनिर्माण के मामले में दुनिया नंबर एक विनिर्माण केंद्र बन जाएगा ... अगर ऐसा होता है तो यह निश्चित रूप से भारत को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में काफी योगदान करेगा।' गडकरी ने कहा कि वर्तमान में वाहन उद्योग 4.5 लाख करोड़ रुपये का है। केंद्रीय

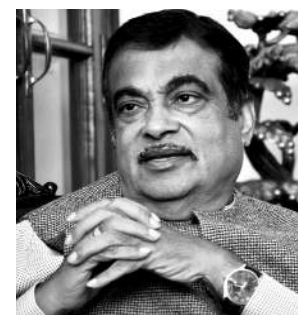

मंत्री ने एक अन्य कार्यक्रम में कहा कि सरकार की अगले पांच साल में खादी एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र के कारोबार को बढ़ाकर दो लाख करोड़ रुपये करने की योजना है। वर्तमान में इसका कारोबार 75,000 करोड़ रुपये है।

उन्होंने उद्योग से वैश्विक कारोबार में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ाकर करीब 10 प्रतिशत करने का आग्रह किया है। साथ ही घरेलू उद्योग से अवसरों को हासिल करने के लिए कहा है। गडकरी ने उद्योग मंडल फिक्की के 92वें वार्षिक सम्मेलन में कहा, 'खादी एवं ग्रामोद्योग का कारोबार वर्तमान में 75,000 करोड़ रुपये है। अगले पांच साल में इसे दो लाख करोड़ रुपये पर ले जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।' *भाषा*

फिच ने जीडीपी वृद्धि अनुमान घटाया

इंदिवजल धस्माना
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

फिच रेटिंग्स ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2019-20 में भारत की आर्थिक वृद्धि का अनुमान घटाकर 4.6 फीसदी कर दिया, जो पहले 5.6 फीसदी था। एजेंसी ने कर्ज उपलब्धता में कमी और कारोबारी एवं उपभोक्ता आत्मविश्वास डगमगाने के कारण पिछली कुछ तिमाहियों में मंदी के कारण यह कदम उठाया है।

फिच ने एक बयान में कहा कि उसकी रेटिंग में यह अनुमान भी शामिल है कि वित्त वर्ष 2019-20 में राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3.3 फीसदी के लक्ष्य से थोड़ा फिसल सकता है। हालांकि एजेंसी ने भारत की सॉवरिन रेटिंग 'बीबीबी-' के न्यूनतम निवेश ग्रेड पर और आउटलुक स्थिर रखा है। फिच का अनुमान है कि आरबीआई 2020 में नीतिगत दरों में 65 आधार अंक की और कटौती करेगा क्योंकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित महंगाई दर नवंबर में बढ़कर 5.5 फीसदी हो गई। इससे खाद्य महंगाई में अस्थायी बढ़ोतरी का पता चलता है। एजेंसी ने कहा कि ऐसा लगता है कि कोर महंगाई पर दबाव वर्तमान माहौल तक सीमित है।

बीएस सूडोकू 3618

	6					3		
	9				4		5	2
		2		6				7
3				4				
9			3		2			5
				5				1
6				3		7		
2	4		8				6	
		8					9	

परिणाम संख्या 3617

2	4	6	1	8	3	7	5	9
5	7	3	9	6	4	8	1	2
1	8	9	7	5	2	3	6	4
8	9	1	6	4	7	5	2	3
7	3	2	5	9	8	6	4	1
4	6	5	3	2	1	9	8	7
9	2	8	4	7	6	1	3	5
6	1	7	2	3	5	4	9	8
3	5	4	8	1	9	2	7	6

कैसे खेलें?
हर रो, कॉलम और 3 बाई 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरें।

मुश्किल
★★★☆☆

गैर-शुल्क बाधाएं पैदा करने वाले देश बताएं: गोयल

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को उद्योग जगत से कहा कि वे उन देशों की जानकारी दें जो देश भारतीय निर्यात की राह में गैर-प्रशुल्कीय बाधाएं खड़ी करते हैं।

उन्होंने कहा कि सरकार ऐसे देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई कर सकती है। उद्योग मंडल फिक्की के 92वें सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने यह भी कहा कि भारत को और प्रतिस्पर्धी होने की जरूरत है। उन्होंने डंपिंग या अनुचित सब्सिडी अथवा उल्टी शुल्क व्यवस्था (तैयार वस्तुओं पर कम आयात शुल्क तथा उन वस्तुओं को बनाने में उपयोग होने वाले कच्चे माल पर अधिक आयात शुल्क) समेत पूरी मूल्य शृंखला की समस्याओं के समाधान पर जोर दिया। गोयल ने कहा, हमारी सरकार किसी एक कंपनी विशेष के मसले के समाधान में भरोसा नहीं रखती बल्कि समस्याओं के मूल कारण को दूर करने में हमारा विश्वास है। समस्या को समझने और उसका टिकाऊ समाधान तलाशने में हमें भरोसा है। इससे कंपनियों की व्यक्तिगत समस्या भी दूर हो जाती है। *भाषा*

क्षेत्रीय मंडियों के भाव

उत्तर प्रदेश | राजस्थान | पंजाब

कानपुर
गेहूं लूज 2100/2120, जौ 1770/1780, चावल मसूरी 2250/2300, चावल मोटा 2150/2225, सरसों 4300/4325, तिल सफेद 9400/9600, सोया (टीन) 1500/1525, तेल सरसों कच्ची घानी वैट पेड (टीन)1600/1670,

लखनऊ
गेहूं दड़ा 2100/2125, गेहूं शरबती 2700/2800, चावल शरबती सेला 3700/3750, स्टीम 4200/4300, लालमती 3300/3400, चावल (सोना) 2900/2975,

चंदौसी
(प्रति किलो): मैन्था ऑयल 1435, बोल्ड क्रिस्टल (12 नं.)1515, फ्लैक 1455, डीएमओ 1050, टरपीन लैस बोल्ड 1545

मुजफ्फरनगर
गुड़ (40 किलो): लड्डू 1230/1265, खुरपा 1140/1165,चाकू 1175/1250, रसकट 870/875, शक्कर 1230/1260, चीनी मिल डिली. (क्विं.) (जीएसटी अतिरिक्त): खतौली3300, सिहोरा 3155, बुढ़ाना 3260, शामली 3215,

हापुड़
गुड़-चीनी: चीनी हाजिर 3550/3600, गुड़ (प्रति 40 किलो) बाल्टी 1000/1050, तिलहन: सरसों (42 प्रतिशत कंडी.) 4500, खल: सरसों 2250/2350, बिनौला 2500/2600, चना छिलका 1950/2000,

जयपुर
अनाज: चावल डीबी 5600/5700, गेहूं (मिल) 2165/2175, मक्की 2200/2225, बाजरा 1840/1850, जौ 1800/1825, ग्वार लूज 3750/3800, ज्वार कैटलफीड 2400/2500, तेल-तिलहन: सरसों(मिल पहुंच) 4690/4700,

श्रीगंगानगर
गेहूं (ढेरी) 2050/2100, ग्वार 3800/3850, जौ 2000/2010,

जोधपुर
गेहूं 2050/2080, जौ 1750/1775, पोपकोन मक्की 4400/4500, ग्वार डिलीवरी (ऑलपेड) 4050/4100, ग्वारगम 7500/7600, बाजरा (गुजरात) 1930/1935, बाजरा (जयपुर) 1890/1900, चना 4200/4250, काबली चना 4800/6000, मूंग 6100/6300,

खन्ना
जीएसटी अतिरिक्त (प्रति क्विं.): राइसब्रान (खाद्य)(प्रति प्वाइंट)125, राइसब्रान (अखाद्य) 122, खल सरसों 2050, डीओसी: राइसब्रान बैच सफेद 1250, लाल 1230, कंटीन्यूअस 1280,

लुधियाना
दाल-दलहन: राजमां चित्रा 7000/8000, अरहर दाल 7700/8300, उड़द साबुत 7300/8000, उड़द धोया 9400/10400, छिलका 9000/10000, दाल मसूर 5700/6000, चनादाल 5400/5600,

अमृतसर
चावल: बासमती (1121 नं.) स्टीम 6100/6200, सेला 5550/5600, शरबती साधारण सेला 3750/3850, शरबती स्टीम 4150/4250,चावल 1509 सेला 5150/5250, धान: शरबती 2100/2150,

बठिंडा
रुई (प्रति मन): जे-34 पंजाब 3970/4000, हरियाणा 3950/3980, राजस्थान 3900/3960, खल (प्रति क्विं.): बिनौला 2400/2500, सरसों खल 2220/2225,

फाजिल्का
गेहूं 2140/2145, सरसों 4450/4475 रुई (प्रति मन): (जे-34) 3900/4000, कपास देशी 4900/5000, कपास नरमा (क्विं.) 5150/5350, बिनौला (टैक्सपेड): खल 2400/2500,

जालंधर
गेहूं दड़ा 2140/2150, चावल परमल कच्चा 2450/2500, से ला 2375/2400, मक्की यूपी 2325/2335, बिहार 2400/2410, दाल उड़द छिलका 8800/10600, चना देशी 5000/5100, दाल चना 5200/5450, काबली चना 4900/5750, राजमां चित्रा पुणे 7000/8300, चीन 7200/7800,

करनाल
गेहूं दड़ा 2145/2155, बासमती चावल 6500/6600, धान 1121 नं. 2900/2925, पूसा 1509 धान 2600/2650, शरबती धान 2150/2200, सेला (1509 नं.) चावल 5200/5300, स्टीम 6000/6150,

हिसार
ग्वार 3800/3850, जौ 1775/1780, सरसों 4200/4250, मूंग 6600/6700, गेहूं 2140/2150,

जींद
जीएसटी अतिरिक्त: गेहूं 2100/2150, आटा (प्रति 44 किलो) 1070/1090, मैदा 1175/1190, देशी घी (एक ली/जार) 370/470, रिफाइंड (टीन) 1385/1400,

भिवानी
जीएसटी अतिरिक्त: सरसों 4250/4300, खल बिनौला मोटी 2300/2500, बिनौला 2800/3200, सरसों तेल 9350/9400, गेहूं 2100/2200, ग्वार 3850/3900, बाजरा 1800/1850 *एनएनएस*

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 12 अंक 262

जीएसटी पर पुनर्विचार

मोदी सरकार ने परिवहन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के विकास और आम नागरिकों के वास्ते उपयोगी वस्तुओं के लिए प्रावधान करने की खातिर महत्त्वाकांक्षी व्यय योजना की शुरुआत की है। दिक्कत इसके लिए धन जुटाने की रही है। एक प्रमुख अनुमान यह था कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लागू होने के बाद सकल घरेलू उत्पाद में अप्रत्यक्ष कर का योगदान बढ़ेगा और इससे मदद मिलेगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ। इस वर्ष जीएसटी से हासिल केंद्रीय राजस्व की बात करें तो वह तय लक्ष्य से करीब 40 फीसदी कम रहा। अब राज्य भी जीएसटी हिस्सेदारी प्राप्त न होने की शिकायत कर रहे हैं। ऐसे में परेशान सरकार अपने बिल का परोक्ष भुगतान करने या शायद न करने के तरीके तलाश रही है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने कहा है कि केंद्र सरकार का घाटा आधिकारिक तौर पर घोषित आंकड़े से कम से कम 2 प्रतिशत अंक अधिक है।

जीएसटी में चार गलतियां की गईं। पहली, राजनीतिक नेतृत्व को लंबे समय तक यह अहसास नहीं हुआ कि जीएसटी परिवर्तन वाला एक सपाट कर है। ऐसे में गरीबों द्वारा ग्रहण की जाने वाली और कर राहत वाली चीजों पर अब अधिक कर दर लगेगी। इसके साथ ही समृद्ध तबके द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वस्तुओं पर कम कर दर लगेगी। यानी यदि जीएसटी दर राजस्व निरपेक्ष रही तो गरीब ज्यादा कर चुकाएंगे और अमीर अपेक्षाकृत कम कर चुकाएंगे। इसके चलते पहली गलती हुई और राजनीतिक कारणों से जीएसटी दरों में भारी बदलाव किया गया। यह बिना जीएसटी के तर्क वाला जीएसटी था।

दूसरी गलती थी राज्यों को एक वर्ष से दूसरे वर्ष में जाने पर जीएसटी राजस्व में 14 फीसदी के इजाफे की गारंटी। ऐसा तब किया गया जब रिजर्व बैंक के लिए मुद्रास्फीति को 4 फीसदी (2 फीसदी इधर-उधर के साथ) पर लक्षित करते हुए मौद्रिक नीति का एक नया ढांचा तय किया जा रहा था। इसका अर्थ यह था कि 7 फीसदी की दर से विकसित होती अर्थव्यवस्था से मुद्रास्फीति को शामिल करते हुए करीब 11 फीसदी की वृद्धि दर देने की उम्मीद थी। यह राज्यों से किए गए 14 फीसदी राजस्व वृद्धि के वादे से काफी कम था। अंतर को पाटने के लिए क्षतिपूर्ति उपकर की व्यवस्था केवल पांच साल के लिए की गई।

साप्ताहिक मंथन
टी. एन. नाइनन

तीसरी गलती थी कई अहम वस्तुओं को जीएसटी के दायरे से बाहर रखना। इसमें पेट्रोलियम उत्पाद, तंबाकू और शराब शामिल हैं। चूंकि उत्पाद राजस्व का बड़ा हिस्सा इन्हीं मदों में आता है इसलिए इसने राजस्व निरपेक्ष जीएसटी दर की संभावना को प्रभावित किया। चौथी गलती थी मोदी सरकार द्वारा आम चुनाव के मद्देनजर वस्तुओं की लागत में कमी करना। इस प्रक्रिया में कई खपत वाली वस्तुओं की कर दर उनके कच्चे माल पर लगने वाली कर दर से भी कम हो गई। ऐसे में अब कंपनियां कच्चे माल पर लगे कर पर रिफंड की मांग कर रही हैं क्योंकि वह उनके द्वारा अंतिम उत्पाद पर चुकाए जाने वाले कर से अधिक है।

इस बीच क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हमें उसी बात को दोहराव देखने को मिला जो तीन साल पहले नोटबंदी के दौरान देखने को मिला था: लोगों ने काले धन को सफेद करने के तमाम तरीके तलाश लिए थे।

जीएसटी के मामले में फर्जी बिल बनाने का एक उद्योग ही चल पड़ा जिसने उत्पादकों को उनकी जरूरत के मुताबिक बिल बनाकर दिए। इस बीच कई उत्पादन शृंखलाओं ने जीएसटी के दायरे से बचने का रास्ता तलाश लिया। शुरुआती वादा कि बिलों का मिलान करके ऐसी धोखाधड़ी रोकी जाएगी, का परीक्षण अप्रैल में होगा। हमें देखना होगा कि क्या ऐसा हो सकता है या इससे भी अफरातफरी ही मचेगी। अगर यह कारगर नहीं हुआ तो जीएसटी का एक प्रमुख वादा झूठा साबित होगा जिसमें कहा गया था कि यह कर वंचना को रोकेगा और जीडीपी में कर हिस्सेदारी बढ़ाएगा।

यदि इनवॉइस मिलाने की प्रक्रिया भी सफल रही तो भी व्यवस्था के कई अन्य तत्त्व ऐसे हैं जो टूटे हुए हैं। शायद जीएसटी की व्यवस्था विकास के मौजूदा चरण में अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जटिल थी। केंद्र को जीएसटी परिषद के साथ मिलकर नई दरें और नए कर स्लैब (जितने कम हों उतना बेहतर) बनाने होंगे तथा एक नई शुरुआत करनी होगी। कोई अर्थव्यवस्था ऐसे कर प्रयोग के साथ नहीं चल सकती जो नाकाम साबित हुआ हो।

अजय मोहंती

मौजूदा मुद्रास्फीति से नहीं हों भयभीत

मौद्रिक नीति फिलहाल सही दिशा में है और वह खुदरा मुद्रास्फीति को 4 फीसदी के तय लक्ष्य में रखने के लिए उपयुक्त कार्य कर रही है। वह इतना ही कर सकती है। विस्तार से बता रहे हैं **अजय शाह**

मुद्रास्फीति में इजाफा हुआ है। सब्जियों की कीमतों में तेज उछाल इसकी अहम वजह है। यह ऐसा समय नहीं है जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के दबाव की ज्यादा चिंता की जाए। रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति के मामले में एकदम सही राह पर है। दिक्कत वित्तीय तंत्र के साथ है: सरकारी बॉन्ड के यील्ड कर्व के शॉर्ट एंड पर आकर्षक ब्याज दर देश के कई उधारकर्ताओं के लिए आकर्षक ब्याज दर में परिवर्तित नहीं हो रही।

खुदरा मूल्य सूचकांक में खाद्य एवं पेय पदार्थों की हिस्सेदारी 45 प्रतिशत है। इस क्षेत्र की मुद्रास्फीति वर्ष 2019 के आरंभ में शून्य से बढ़कर नवंबर में 8.7 फीसदी हो गई। इससे कुल खुदरा मुद्रास्फीति को बढ़ाने में मदद मिली है और यह 3 फीसदी से बढ़कर 5.5 फीसदी हो गई। कई लोग मौद्रिक नीति के भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

यहां तक कि आदर्श स्थितियों में भी मौद्रिक नीति एक लंबे अंतराल के साथ काम करती है। ऐसे में जब हम मौद्रिक नीति समिति के निर्णयों के बारे में सोचते हैं तो हमें अतीत की सूचनाओं में देरी पर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए। हमें भविष्य पर दृष्टि डालनी चाहिए और देखना चाहिए कि सन 2020 के आखिर तक अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति रहेगी। क्योंकि मौद्रिक नीति उसे प्रभावित करने में कारगर हो सकती है। मौजूदा महंगाई में सब्जियों की अहम भूमिका है। खुदरा मूल्य सूचकांक में सब्जियों की हिस्सेदारी 6 फीसदी है। नवंबर में इस क्षेत्र में सालाना आधार पर मुद्रास्फीति 36 फीसदी रही। परंतु सब्जियों को कीमतों में तेज उतार-चढ़ाव के लिए जाना जाता है। मसलन टमाटर की बुआई से उपज तक का समय 90 दिन का है। ऐसे में आपूर्ति के कारण कीमतों में तेजी से उतार-चढ़ाव आता है।

सब्जियों की कीमतों में पिछली उछाल 2017 के अंत में आई थी। दिसंबर 2017 में सब्जियों में मुद्रास्फीति 29 प्रतिशत थी। परंतु इसके पश्चात तत्काल आपूर्ति संबंधी प्रतिक्रिया हुई और सब्जियों की कीमतें जुलाई तक दोबारा ऋणात्मक हो गईं।

जब टमाटर की कीमतों में तेजी आई तो लोगों ने वैयक्तिक स्तर पर टमाटर की खेती का रकबा बढ़ाया। कई अन्य प्रतिक्रियाएं भी सामने आईं। लोगों ने कृषि क्षेत्र में कच्चे माल का इस्तेमाल बढ़ाया और एक खास सीमा के बाद उपज का ध्यान रखा। परिणामस्वरूप जब कीमतें ज्यादा होती हैं तो वैयक्तिक स्तर पर लोग बिजली और डीजल या शीतगृहों के भुगतान पर अधिक व्यय करते हैं ताकि उपज के अवमूल्यन की दर कम की जा सके। व्यवहार में यह बदलाव उस खेत के प्रति भी होता है जहां पहले बुआई की गई थी। यदि टमाटर का कोई पौधा 60 दिन पुराना है और बाजार में टमाटर की कीमत अच्छी मिल रही है तो इस बिंदु पर फसल की बेहतरी के लिए काफी प्रयास किए जाते हैं ताकि अंतिम आपूर्ति प्रतिक्रिया में अंतर किया जा सके।

इस बात की संभावना रहती है कि ऐसा दोबारा होगा। नवंबर में सब्जियों की उच्च मुद्रास्फीति के चलते आपूर्ति प्रतिक्रिया शुरू हुई और कुछ ही महीनों में सब्जियों की महंगाई दोबारा कम हो जाएगी। ऐसे में आज मौद्रिक नीति विचार में असल मुद्दा 2020 के आखिर में खुदरा मूल्य सूचकांक के पूर्वानुमानों पर विचार करना है। जाहिर है नवंबर 2019 की ऊंची कीमतों का ज्यादा असर 2020 के आखिर के पूर्वानुमानों पर नहीं पड़ना चाहिए।

मौद्रिक नीति ढांचे के डिजाइन में इन पहलुओं को अच्छी तरह समझा गया था। यही कारण है कि लक्षित दायरा 2 फीसदी से 6 फीसदी के बीच रखा गया, बजाय कि 4 फीसदी के। हमें आरबीआई को 4 फीसदी खुदरा मुद्रास्फीति के लिए जवाबदेह ठहराना चाहिए लेकिन उम्मीद करनी चाहिए कि 2 से 6 फीसदी के दायरे में और अधिक उतार-चढ़ाव नजर आएंगे। संक्षेप में कहा जाए तो जब हम 2 फीसदी से कम या 6 फीसदी से अधिक का उतार-चढ़ाव देखते हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि उक्त गलतियां एक वर्ष या दो वर्ष से अधिक पहले की होंगी और हमें इन्हें बेहतर ढंग से समझने के लिए इस पर करीबी नजर डालनी होगी कि आखिर गलती कहां हो गई और प्रक्रिया में कैसे सुधार किया जा सकता है?

मौद्रिक नीति के कई उपकरण हैं इसलिए शीर्ष मौद्रिक नीति यानी रीपो दर और रिवर्स रीपो दर से परे नजर डालने की भी आवश्यकता है। मौद्रिक नीति के तमाम उपकरण साथ आते हैं और 91 दिन के ट्रेजरी बिल की शर्तें निर्धारित करते हैं। मौद्रिक नीति के मामले में ब्याज दर सबसे सटीक तरीके से यह व्याख्या करती है कि वह कैसे काम करती है। सन 2018 के आरंभ में मौद्रिक नीति समिति को लगा कि सख्ती की आवश्यकता है और उसने दरों में 100 आधार अंक की बढ़ोतरी की दी। सात प्रतिशत के इस उच्चतम स्तर से उसने करीब 300 आधार अंकों की कटौती की।

ऐसे में वास्तविक तौर पर नीतिगत दर करीब एक फीसदी है जो सही प्रतीत होता है। अर्थव्यवस्था में एक दिक्कत है कि कर्जदार बहुत ऊंची दरों पर भुगतान कर रहे हैं। यह मौद्रिक नीति नहीं बल्कि वित्तीय नीति की समस्या है। भविष्य में दरों में कटौती की गुंजाइश है। मुझे संदेह है कि नीतिगत दरों में आगे और कटौती होगी। अल्पावधि में मौद्रिक नीति के रुख में बदलाव अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा अंतर नहीं पैदा करेगा क्योंकि पहले ही काफी ऊंची ब्याज दर चुकाई जा रही है।

अर्थव्यवस्था में आज ब्याज दर के कई अनुमान ऐसे मूल्य पर हैं जो 4 फीसदी के मुद्रास्फीति लक्ष्य से दूर हों। जरूरत यह है कि प्रतिफल की प्रशासित दर 5 फीसदी के आसपास हो लेकिन वह 8 से 9 फीसदी के बीच है। नॉमिनल जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान, जिन्हें बजट प्रक्रिया में शामिल किया जाता है उन्हें कम करने की आवश्यकता है। इन्हें तत्काल कम करना व्यवहार्य भी है और इससे काफी मदद भी मिलेगी।

अर्थव्यवस्था की असल दिक्कत है कमजोर कारोबारी चक्र की परिस्थितियों का वृद्धि में गिरावट के रुझान पर परिलक्षित होना। हमने सन 1991 से 2011 के बीच उच्च वृद्धि का दौर देखा। परंतु उसके बाद इसमें धीमापन आ गया। मौद्रिक नीति कारोबारी चक्र में आ रहे उतार-चढ़ाव से निपटने का अच्छा तरीका है लेकिन वृद्धि के रुझान में गिरावट से निपटने का नहीं। व्यापक तौर पर देखें तो आज मौद्रिक नीति सही दिशा में है। वह 4 फीसदी की खुदरा मुद्रास्फीति को लेकर सही प्रदर्शन कर रही है। मौद्रिक नीति ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है। हमें मुद्रास्फीति में हालिया बढ़ोतरी की चिंता नहीं करनी चाहिए। न ही मौद्रिक नीति के मौजूदा आचरण की।

नफरत की आग भड़का रहे भारतीय समाचार चैनल

मीडिया मंत्र
वनिता कोहली-खांडेकर

भारत के लिए यह हफ्ता रक्तरंजित रहा है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इनमें से कुछ प्रदर्शनों ने हिंसा का रूप ले लिया। ऐसा लगता है कि टेलीविजन चैनलों, समाचारपत्रों और सोशल मीडिया के शोरशराबे में यह बात कहीं गुम हो गई कि ऐसा क्यों और कैसे हुआ?

मीडिया खासकर टीवी इस कानून के बारे में जानकारी देने, लोगों को जागरूक करने और उनके उमड़ते जज्बात को शांत करने में नाकाम रहा है। इस कानून से क्या होगा? अपनी नागरिकता साबित करने का क्या मतलब है? समाचारपत्रों, एक-दो समाचार चैनलों और करीब आधा दर्जन समाचार वेबसाइट को छोड़कर बाकी सभी मीडिया प्रतिष्ठानों ने इस मुद्दे की रिपोर्टिंग में बेहद खराब काम किया है।

भारत में टीवी की पहुंच 83.6 करोड़ लोगों तक है जबकि इंटरनेट उपभोक्ता 66 करोड़ और समाचारपत्र पाठक 40 करोड़ ही हैं। टीवी दर्शक अनुसंधान परिषद बार्क के आंकड़े बताते हैं कि समाचार चैनलों की पहुंच 26 करोड़ से अधिक दर्शकों तक है। इसके साथ 5-10 करोड़ उन लोगों को भी जोड़ लीजिए जो ऑनलाइन माध्यमों से समाचार चैनल देखते हैं। वर्ष 2000 में जहां भारत में मुश्किल से दस समाचार चैनल थे, वहीं अब यह संख्या दुनिया में सर्वाधिक 400 के पार हो चुकी है। इनमें से आधे समाचार चैनलों का स्वामित्व रियल एस्टेट दिग्गजों, नेताओं और उनके सहयोगियों के पास है। मांग से अधिक चैनल वाला यह बाजार पूरी तरह विज्ञापन पर निर्भर है। विज्ञापन अधिक दर्शकों वाले चैनलों के ही खाते में जाते हैं। इसका नतीजा यह है कि बीते दशक में गुणवत्ता लगातार नीचे की तरफ गिरती चली गई। इस होड़ में बलात्कार एवं हत्या को सांप्रदायिक रंग देने से लेकर हिंसा के लिए उकसाने जैसी सभी बातें सही मान ली जाती हैं। अहम मसलों पर भारतीय समाचार चैनलों की नादानी एवं कायरता एकदम साफ नजर आती है। मसलन, अर्थव्यवस्था की गिरती सेहत और बढ़ती आय असमानता के मुद्दों पर अधिकतर चैनल चुप रहते हैं।

यूट्यूब पर पीइंग ह्यूमन चैनल चलाने वाले रमित वर्मा मीडिया एवं समसामयिक मुद्दों पर अपना नजरिया पेश करते हैं। इस साल 19 अक्टूबर तक देश के चार बड़े हिंदी समाचार चैनलों पर प्रसारित चार प्रमुख टीवी शो में होने वाली बहसों का उनका विश्लेषण बहुत कुछ बयां कर देता है। इस दौरान इन चैनलों पर प्राइम टाइम में हुई 202 बहसों में से 79 पाकिस्तान पर हमले से संबंधित थीं जबकि 66 बहसों के केंद्र में विपक्षी दल और जवाहरलाल नेहरू थे। हजारों जमाकर्ताओं की जिंदगी भर की बचत जिस पीएमसी बैंक के डूबने से खतरे में पड़ चुकी है, उस बारे में महज एक बहस हुई। शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, पर्यावरण, भीड़ की हिंसा, अर्थव्यवस्था या किसानों की बदहाली पर कोई भी चर्चा नहीं हुई। पाकिस्तान जैसे अप्रासंगिक देश को लेकर समाचार चैनलों में छाई सनक को पेचीदा मानकर खारिज किया जा सकता है लेकिन इसका असर वास्तविक है।

समाचार चैनलों पर परोसा जाने वाला कचरा सोशल मीडिया और व्हाट्सऐप संदशों की शक्ल में विस्तार पा लेता है। फिर सम्मेलनों और डाइनिंग रूम में उन्हें उद्धृत किया जाता है। इस तरह वह ऐसे उत्पाद में बदल जाता है जो हमारे राजनीतिक एवं सामाजिक निर्णयों को बदलने लगता है। इस वजह से होने वाला ध्रुवीकरण, भारतीयता की हमारी सामूहिक भावना और ज्ञान के स्तर को होने वाली क्षति उस समय नजर आती है जब लोग निहत्थे छात्रों की पिटाई करने वाली पुलिस के पक्ष में भी तालियां पीटने लगते हैं। तमाम भारतीय अभी इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि वे बड़ी मुश्किल से हासिल एवं सींचे गए लोकतंत्र की कुछ आखिरी निशानियों की मौत पर जश्न मना रहे हैं।

वित्तीय रूप से इनमें से किसी भी चैनल का अधिक प्रभाव नहीं है। समाचार टीवी चैनलों का बाजार महज 3,000-4,000 करोड़ रुपये है जबकि टीवी उद्योग का आकार 74,000 करोड़ रुपये है। इतने चैनलों में से बमुश्किल दो चैनल ही लाभ कमाते हैं। लेकिन समाचार चैनलों ने सामाजिक रूप से उस भारत को तबाह कर दिया है जिसकी सारी दुनिया विविधता को जगह देने के लिए तारीफ करती रही है। सवाल उठता है कि क्या किया जा सकता है? इस स्तंभ में पहले भी सुझाए जा चुके बिंदुओं में तीन काफी अहम हैं। पहला, दूरदर्शन और आकाशवाणी का संचालन करने वाले प्रसार भारती कॉर्पोरेशन को केंद्र सरकार से वित्तीय एवं प्रशासनिक तौर पर स्वतंत्र किया जाए। इसे बीबीसी की तर्ज पर एक विश्वस्तरीय सार्वजनिक प्रसारक बनने के लिए करदाताओं के पैसे का इस्तेमाल करने दीजिए। ब्रिटेन में बीबीसी ऐसे मानदंडों का मानक तय करता है जिसके अनुसरण के लिए निजी चैनल बाध्य होते हैं।

दूसरा, समाचार प्रसारण में विदेशी निवेश के स्तर को 49 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी किया जाए। अधिकांश विदेशी समाचार प्रसारक इसके लिए अधिक इच्छुक नहीं नजर आते हैं। लेकिन अगर कुछ प्रसारक भारत आते हैं और प्रशिक्षण एवं रिपोर्टिंग में निवेश करते हैं तो यह काफी अच्छा होगा। भारतीय समाचार चैनलों के तेजी से बढ़ने का सबसे बड़ा नुकसान यह हुआ है कि जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग खत्म हो चुकी है और पूरी व्यवस्था एंकरों के इर्दगिर्द संचालित हो रही है।

तीसरा, चैनलों के स्वामित्व मानकों को बदलिए। यह इसलिए अहम है कि अगर गुणवत्तापरक पत्रकारिता और अन्य दबावों में से चुनने का मौका आता है तो मालिक किसे तरजीह देंगे? सबसे अच्छे एवं मुनाफे में चलने वाले वैश्विक समाचार ब्रांड का स्वामित्व ऐसी कंपनियों के पास है जिसकी कमान ट्रस्ट संभालता है। जैसे, द इकनॉमिस्ट, द न्यूयॉर्क टाइम्स और फाइनैंशियल टाइम्स।

अगर भारतीय सिनेमा ने हमारी सॉफ्ट पावर का प्रतीक बनकर हमें वैश्विक गौरव दिया है तो भारतीय समाचार चैनलों ने सबसे खराब पत्रकारिता से हमें शर्मसार भी किया है। अब समस्या दूर करने का वक्त आ गया है।

कानाफूसी

बल्लेबाजी को तैयार

मध्य प्रदेश की बुरहानपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह 'शेरा' को उनकी बागी तबियत के लिए जाना जाता है। वह मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार का समर्थन कर रहे हैं लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया इसलिए वह नाखुश भी हैं। यही कारण है कि वह अक्सर राज्य सरकार की आलोचना के कारण सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान जब उन्हें मुख्यमंत्री कमल नाथ के साथ देखा गया तो यह सवाल भी उठा कि क्या उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है? इसके जवाब में सिंह ने कहा, 'कमल नाथ मेरे कप्तान हैं। जब भी वह मुझसे बल्लेबाजी करने के लिए कहेंगे, मैं मैदान पर उतर कर चौके-छक्के लगाना शुरू कर दूंगा।'

सीएए के दौर में गांधी

नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) के विरोध में भड़की आग अब देश के हर हिस्से में फैल चुकी है। सरकार के प्रवक्ता और जनता से जुड़े मंच जहां इस विषय पर अपनी-अपनी बात कह रहे हैं, वहीं पत्र सूचना कार्यालय बीती 18 दिसंबर से ही लगातार महात्मा गांधी के उद्धरण ट्वीट कर रहा है। इन उद्धरणों का उक्त तारीख या किसी घटना के साथ तारतम्य भी नहीं है। एक ट्वीट में कहा गया है कि हमें दूसरों से अच्छाई ग्रहण करनी चाहिए और बुराई को छोड़ देना चाहिए। एक अन्य ट्वीट में कहा गया है कि हम अंग्रेजी शासन के अधीन इसलिए भी हुए क्योंकि हममें जागरूकता की कमी थी। इसी तरह एक अन्य ट्वीट में कहा गया है कि अच्छा परिणाम हमेशा सही तौर तरीकों से ही मिल सकता है। गलत और गैर ईमानदार तरीके अच्छा परिणाम नहीं दे सकते।

आपका पक्ष

शांति के पथ पर अग्रसर घाटी

जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म करने तथा जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने के बाद वहां आतंकी घुसपैठ में कमी आई है। आए दिन सेना पर पथराव की घटनाओं में भी खासी कमी आई है। सरकार के अनुसार इस साल अब तक पथराव की 544 घटनाएं हुईं जिनमें 190 राज्य का विशेष दर्जा खत्म करने के बाद हुईं। वर्ष 2018 में पथराव की 802 घटनाएं हुई थीं। इससे जाहिर है कि केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद राज्य में हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। घाटी में कुछ पाबंदी लगी हुई है जिससे सरकार को आंतकी गतिविधियों को नाकाम करने तथा लोगों द्वारा पथराव की घटनाओं को कम करने में मदद मिली है। केंद्र शासित प्रदेश बनने से पहले घाटी में तकरीबन रोजाना विरोध प्रदर्शन होते थे और भारत सरकार के खिलाफ वहां के लोगों को भड़काये जाते थे। अलग राज्य बनने के बाद ऐसे उपद्रवी लोगों को नजरबंद किया गया या फिर जेल भेजा गया जिसके बाद अब घाटी में अमन चैन है। हालांकि राज्य में स्थिति सामान्य होने में कुछ वक्त लग सकता है लेकिन एक बात जाहिर है कि वहां के असामाजिक तत्त्वों द्वारा कोई बड़ी घटना को अंजाम नहीं दिया गया है। कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है और अब वक्त आ गया है कि सभी देशवासियों को इस धरती के स्वर्ग को और बेहतर बनाने के लिए प्रयास किया जाए।

गायत्री कुमारी, मंडी

जम्मू कश्मीर में पथराव की घटनाओं में इन दिनों काफी कमी आई है *फाइल फोटो*

देश में वन रक्षकों की काफी कमी

वन्य प्राणियों के अपने आश्रय स्थल छोड़ने की घटनाएं हाल के वर्षों में बढ़ गई है। वे राष्ट्रीय मार्गों, शहरी इलाकों में दिखाई देने लगे हैं। इसका एक कारण तो वन रक्षकों की कम संख्या हो सकता है। दूसरा घटता हुआ वन क्षेत्र भी हो सकता है। केंद्र सरकार इन दोनों स्थितियों पर राज्यवार सर्वेक्षण करे। किस राज्य में वन क्षेत्र तेजी से कम हुआ है तथा ऐसा किन कारणों से हुआ है। साथ ही वन रक्षकों की संख्या बल वन क्षेत्र के अनुपात में कहां कम है और कहां पर्याप्त बल होते हुए भी वन एवं वन्य प्राणियों की अभिरक्षा में कोताही बरती गई है। नक्सल प्रभावित वनों का ऐसा आकलन अलग से होना चाहिए। जाहिर है वन क्षेत्र राष्ट्र की अनमोल विरासत और कीमती संपत्ति है। इसके संवर्द्धन और समृद्धि का दायित्व केवल वन विभाग की ही नहीं है। विभाग को तो वन्य जीवन प्रेमियों, स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं को अधिक प्रेरित व प्रोत्साहित करना चाहिए।

हिम्मत जोशी, नागपुर

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिजनेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली - 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

अगले साल भी महंगा बिकेगा आलू

प्रतिकूल मौसम से नए आलू की पैदावार घटने की संभावना

रामवीर सिंह गुर्जर
नई दिल्ली, 20 दिसंबर

आलू उत्पादन

- नई आवक से थोक में घटने लगे भाव, खुदरा भाव तेज बने हुए हैं
- नई आवक से अगले महीने तक सामान्य होंगे आलू के दाम
- दिल्ली में 34 रुपये, भोपाल में 22 रुपये, लखनऊ में 22 रुपये और अमृतसर में 15 रुपये बिक रहा
- वर्ष 2018-19 में 530 लाख टन आलू पैदा हुआ जो इसके पिछले साल से 17 लाख टन ज्यादा है
- 10 प्रतिशत वर्ष 2019-20 में घट सकता है आलू का उत्पादन

अगले साल उपभोक्ताओं को इस साल की तुलना में आलू की ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती हैं क्योंकि प्रतिकूल मौसम से आलू की नई फसल कमजोर है। हालांकि आलू की कीमतों में भारी तेजी के बाद अब दिल्ली की मंडियों में इसके दाम गिरने शुरू हो गए हैं। मगर खुदरा बाजार में कीमतें ऊंची बनी हुई हैं। बारिश के कारण आलू की नई फसल में देरी और कुछ उत्पादक इलाकों में हुए नुकसान के कारण आलू के दाम तेजी से बढ़े हैं। अगले महीने के आखिर तक आलू की कीमतें सामान्य होने की उम्मीद की जा रही है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के मुताबिक शुक्रवार को दिल्ली में आलू की खुदरा कीमत 34 रुपये, भोपाल में 22 रुपये, लखनऊ में 22 रुपये और अमृतसर में 15 रुपये प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। थोक भाव घटने के बाद भी दिल्ली के खुदरा बाजार में आलू के दाम ऊंचे स्तर पर बने हुए हैं।

दिल्ली की आजादपुर मंडी स्थित पोटेटो अनियन मर्चेंट एसोसिएशन (पोमा) के अध्यक्ष त्रिलोकचंद शर्मा कहते हैं कि पहले खेतों में आलू लगाने और फिर आलू निकालते वक्त बारिश होने से फसल कमजोर है। साथ ही मंडियों में नए आलू की आवक में देरी भी हुई है। बीते कुछ वर्षों से घाटा झेल रहे किसानों ने इस बार आलू की फसल कम लगाई है। प्रतिकूल मौसम से नई फसल कमजोर है और इसमें देरी होने के कारण आलू के दाम अचानक तेजी से बढ़ गए थे।

दिसंबर में पंजाब से ज्यादातर नया आलू आता है। अब पंजाब से नए आलू की आवक बढ़ने के कारण दो दिन से आलू के दाम 100 से 200 रुपये तक गिरकर 1,400 से 2,200 रुपये प्रति क्विंटल पर आ चुके हैं। इससे पहले यह 2,400 रुपये तक पहुंच गए थे। मंडी में दो-तीन दिन से नए आलू की 40 से 50 गाड़ियां आ रही हैं जबकि पहले आवक 10 से 15 गाड़ी ही थी। ऊंचे भाव पर स्टोर वाले और नए आलू की दूसरे राज्यों खासकर दक्षिण भारत से मांग कमजोर पड़ गई है। जिससे गुरुवार को आई 150 गाड़ियों में से 64 गाड़ी आलू की बिक्री ही नहीं हुई।

शर्मा कहते हैं कि इस माह के आखिर तक आलू के दाम 1,400-1,600 रुपये प्रति क्विंटल तक और अगले माह के आखिर तक 1,000 से 1,200 रुपये क्विंटल के स्तर तक आ सकते हैं।

फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष राजेश गोयल कहते हैं कि प्रतिकूल मौसम के कारण नए आलू का उत्पादन 10 फीसदी घटने का अनुमान है। आलू किसान इस समय चल रहे ऊंचे भाव का लाभ उठाने के लिए भंडारण के लिए आलू पकने का इंतजार किए बिना इसे अभी बेचने पर जोर देंगे। इस वजह से और कम उत्पादन के कारण अगले साल आलू का भंडारण भी कम हो सकता है। ऐसे में अगले साल आलू के दाम इस साल की तुलना में ज्यादा रहने की संभावना है। शर्मा भी अगले साल आलू महंगा होने का अनुमान लगा रहे हैं।

गोयल ने आलू कीमतों के बारे में कहा कि अब पंजाब और दूसरे उत्पादक राज्यों से देरी वाली खरीफ आलू की नई फसल की आवक बढ़ने लगी है और अगले माह से रबी सीजन वाले आलू की आवक भी जोर पकड़ेगी। ऐसे में अगले डेढ़ महीने में आलू के दाम सामान्य होने के आसार हैं।

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2018-19 में 530 लाख टन आलू पैदा हुआ है, जो इससे पहले वाले वर्ष की तुलना में करीब 17 लाख टन ज्यादा है। कारोबारी अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019-20 में आलू उत्पादन 10 फीसदी घट सकता है।

महाराष्ट्र: कपड़ा इकाइयों को सस्ती बिजली

दिलीप कुमार झा
मुंबई, 20 दिसंबर

महाराष्ट्र में कपड़ा इकाइयों को बड़ी राहत देते हुए सरकार उन्हें बिजली सब्सिडी देने जा रही है। सरकार राज्य में पावरलूम, कताई मिलों और कपड़ा इकाइयों को प्रति यूनिट 3.77 रुपये की दर से बिजली सब्सिडी देने जा रही है।

कपड़ा इकाइयां अपनी कमजोर बैलेंस शीट के कारण कार्यशील पूंजी जुटाने को लेकर संघर्ष कर रही हैं। इनमें छोटे और मध्य आकार वाली इकाइयों की संख्या अधिक है। इनमें से बहुत-सी इकाइयों ने घरेलू बाजार की कमजोर मांग और निर्यात में तीव्र गिरावट के कारण अपनी परिचालन क्षमता का कुछ हिस्सा बंद कर दिया था।

कपड़ा मूल्य शृंखला की उत्पादन लागत में करीब आधा हिस्सा बिजली का होता है। एक ओर जहां पूरे भारत में कताई मिलें कपास की बढ़ी हुई कीमतों का बोझ उपभोक्ताओं पर डालने को लेकर संघर्ष कर रही हैं, वहीं वस्त्र निर्माताओं के सामने गिरते निर्यात की चुनौती है। देश में जारी आर्थिक सुस्ती से कपड़े और सिले-सिलाए वस्त्रों की घरेलू मांग कम हो गई है जिससे लाभ मार्जिन में लगातार गिरावट आ रही है। महाराष्ट्र सरकार की कपड़ा आयुक्त माधवी खोडे चवड़े ने वस्त्र और कपड़ा विनिर्माताओं के मेले से इतर बातचीत में कहा, 'हमने पावरलूम और वस्त्र मूल्य शृंखला में दूसरी इकाइयों को प्रति यूनिट 3.77 रुपये की सब्सिडी देनी शुरू कर दी है। इस सब्सिडी की घोषणा सरकार ने की थी। पैसा जारी होने से निश्चित तौर पर राज्य में कपड़ा और वस्त्र इकाइयों को फायदा होगा।'

भारत सरकार के कपड़ा मंत्रालय में अतिरिक्त आयुक्त अजीत चव्हाण ने कहा,

छोटे और मध्यम आकार की कपड़ा इकाइयां अपने कमजोर बही खाता के कारण कार्यशली पूंजी जुटाने के लिए कर रही हैं संघर्ष

'महाराष्ट्र में सोलापुर दुनिया के एकमात्र यूनिफॉर्म (वर्दी) केंद्र के तौर पर उभरा है। लेकिन इस केंद्र की निर्माण इकाइयों को निर्यात पर ध्यान देने की जरूरत है।'

सोलापुर गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एसजीएमए) के निदेशक अमित कुमार जैन ने कहा, 'वर्दी निर्माण उद्योग अपेक्षाकृत तीव्र गति से बढ़ रहा है और यह मौजूदा 18,000 करोड़ रुपये की जगह 2024 तक 25,000 करोड़ रुपये का क्षेत्र बन सकता है।' राज्य सरकार ने राज्य में सहकारी कताई मिलों के लिए तीन रुपये प्रति यूनिट तथा बुनाई, वस्त्र और होजरी की बड़ी इकाइयों के लिए दो रुपये प्रति यूनिट की बिजली सब्सिडी देने की घोषणा की है जिसके लिए 150 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस बीच इक्रा के एक अध्ययन में कहा गया कि कताई मिलों के राजस्व में छह फीसदी की गिरावट आ सकती है। इस अध्ययन में कहा गया है कि अन्य उत्पादक देशों से मिल रही प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और घरेलू खपत में सुस्ती के बीच कमजोर निर्यात मांग के कारण वित्त वर्ष 2020 की पहली छमाही में उत्पादन और प्राप्ति दोनों पर दबाव देखा जा रहा है।

घरेलू कच्चे माल की अधिक लागत के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय कपास के मुकाबले घरेलू कपास के अधिक दामों के कारण भी निर्यात की प्रतिस्पर्धी क्षमता को चोट पहुंची है। अक्टूबर 2019 के दौरान निर्यात में दिखे सुधार से आगामी तिमाहियों में उद्योग को सूती धागा निर्यात के संबंध में उम्मीद दिख रही है। उनकी इस उम्मीद को घरेलू स्तर पर कपास की कीमतों में आई कमी से भी बल मिला है।

घरेलू कताई मिलों को आशंका है कि वित्त वर्ष की पहली छमाही में कम बिक्री और कमजोर कमाई से वित्त वर्ष 2020 में प्रदर्शन पर असर पड़ेगा। घरेलू कपास कताई उद्योग पर इक्रा के हालिया सर्वेक्षण के नतीजों के मुताबिक यह परिदृश्य अनुमान के मुताबिक ही है। उद्योग सुस्ती से उबर रहा है।

इक्रा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और समूह प्रमुख (कॉर्पोरेट सेक्टर रेटिंग्स) जयंत राय ने कहा, 'मई से सितंबर 2019 के दौरान निर्यात में तीव्र गिरावट के बाद हाल के महीनों में निर्यात में कुछ उछाल जरूर दिखाई दी है, लेकिन वह पिछले वित्त वर्ष के स्तर से नीचे ही रही। सर्वेक्षण में शामिल लोगों ने राजस्व में पांच फीसदी से अधिक की गिरावट और वित्त वर्ष 2020 में परिचालन लाभ में तीन फीसदी तक की कमी की आशंका जताई है।'

उन्होंने कहा कि निर्यात में उछाल और नया सत्र शुरू होने पर कपास की कीमतें नीचे आने से आगामी तिमाहियों में कताई मिलों के प्रदर्शन में सुधार आने के आसार हैं।

अंतरराष्ट्रीय और घरेलू भाव

As on Dec 20	International Price	International %Chg#	Domestic Price	Domestic %Chg#
METALS ($/tonne)				
Aluminium	1,765.5	0.0	1,912.3	-3.8
Copper	6,161.0	6.6	6,439.8	3.1
Nickel	14,035.0	-21.9	14,763.8	-18.8
Lead	1,896.5	-10.0	2,221.6	6.5
Tin	17,300.0	5.3	18,068.1	0.2
Zinc	2,324.0	0.6	2,601.2	-0.2
Gold ($/ounce)	1,479.1*	-2.5	1,660.5	1.3
Silver ($/ounce)	17.1*	-5.0	19.4	-3.2
ENERGY				
Crude Oil ($/bbl)	67.4*	4.3	66.8	3.7
Natural Gas ($/mmBtu)	2.3*	-8.3	2.3	-8.5
AGRI COMMODITIES ($/tonne)				
Wheat	188.6	11.2	302.0	6.0
Maize	181.8*	1.1	333.0	13.0
Sugar	358.0*	9.9	484.0	-1.9
Palm oil	720.0	35.2	1,131.9	29.5
Rubber	1,594.6*	4.6	1,842.0	2.5
Coffee Robusta	1,347.0*	4.7	1,870.1	-9.7
Cotton	1,491.0	14.4	1,583.9	-3.6

* As on Dec 20, 19 1800 hrs IST, # Change Over 3 Months, Conversion rate 1 USD = 71.1& 1 Ounce = 31.1032316 grams.

Notes:
1) International metals, Indian basket crude, Malaysia Palm oil, Wheat LIFFE and Coffee Karnataka robusta pertains to previous days price. 2) International metal are LME Spot prices and domestic metal are Mumbai local spot prices except for Steel. 3) International Crude oil is Brent crude and Domestic Crude oil is Indian basket. 4) International Natural gas is Nymex near month future & domestic natural gas is MCX near month futures. 5) International Wheat, White sugar & Coffee Robusta are LIFF E future prices of near month contract. 6) International Maize is MATIF near month future, Rubber is Tokyo-TOCOM near month future and Palm oil is Malaysia FOB spot price. 7) Domestic Wheat & Maize are NCDEX future prices of near month contract, Palm oil & Rubber are NCDEX spot prices. 8) Domestic Coffee is Karnataka robusta and Sugar is M30 Mumbai local spot price. 9) International cotton is Cotton no.2-NYBOT near month future & domestic cotton is MCX Future prices near month tures.

Bloomberg chartMaker — Compiled by BS Research Bureau

एमसीएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	61.7	12740
Oil and Oilseeds	175.4	81708
Spices	1.0	15
Metal(Dec 19)		
Metal- non ferrous	5447.9	60809
Metal- precious	8181.5	431
Oil and gas(Dec 19)		
Gas	3205.0	46688
Oil	9308.3	2832

एनसीडीईएक्स

Name	Tovr (₹ Cr)	OI(000)
Agri commodity		
Cotton	221.2	107993
Grains	305.5	100905
Oil and Oilseeds	856.2	512885
Others	163.0	69540
Pulses	68.3	51350
Spices	98.5	28301

एमसीएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
Nickel (Dec 31)	1036.5	2.5
Crude Palm Oil (Dec 31)	737.4	0.8
Silver Mini (Feb 28)	44818.0	0.8
Silver Micro (Feb 28)	44817.0	0.8
Silver (Mar 05)	44796.0	0.8
Aluminium (Dec 31)	134.5	0.5
Losers (* % Change)		
Cardamom (Jan 15)	3213.2	-1.4
Natural Gas (Dec 26)	160.7	-0.9
Mentha Oil (Dec 31)	1288.4	-0.5
Lead Mini (Dec 31)	153.2	-0.2
Lead (Dec 31)	153.2	-0.2
Cotton (Dec 31)	19150.0	-0.1

एनसीडीईएक्स बढ़ा/घटा

Name (Maturity)	Close	Day*
Gainers (* % Change)		
CottonSeed Oil-Akola (Dec 20)	2135.0	2.1
Chana-Bikaner (Dec 20)	4506.0	1.5
Soyabean Indore (Dec 20)	4350.0	1.1
Jeera Unjha (Jan 20)	16150.0	0.8
Guar Seed 10 (Dec 20)	4180.0	0.6
Shankar Kapas-Rajkot (Apr 30)	1111.0	0.5
Mustard Seed Rape Oil (Jan 20)	4605.0	0.4
Ref Soy Oil-IDR-2016 (Dec 20)	887.0	0.2
Coriander-Kota (Dec 20)	6988.0	0.1
Losers (* % Change)		
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6134.0	-2.0
CastorSeed New-Disa (Dec 20)	4324.0	-0.8

एमसीएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Cotton-Rajkot (Dec 31)	19150.0	1.9
Gold Petal-Mumbai (Dec 31)	3869.0	1.5
Silver Micro-Ahemd (Feb 28)	44817.0	1.3
Silver Ahm (Mar 05)	44796.0	1.3
Cardamom Vandanmedu (Jan 15)	3213.2	0.6
Gold Ahm (Feb 05)	38109.0	0.4
Discount over spot price (In %)		
Menthol Oil Chandaus (Dec 31)	1288.4	-8.3
Aluminium Mum (Dec 31)	134.5	-4.0
Alumini-Mumbai (Dec 31)	134.5	-4.0
Copper Mum (Dec 31)	445.7	-2.0
Zinc Mini Mumbai (Dec 31)	183.4	-0.9
Nickel Mumbai (Dec 31)	1036.5	-0.8

एनसीडीईएक्स बढ़त/छूट

Name (Maturity)	Futures	Prem/Dis
Premium over spot price (In %)		
Bajra-Jaipur (Jan 20)	2050.0	2.5
Coriander-Kota (Dec 20)	6988.0	1.7
Turmeric Nizamabad (Dec 20)	6134.0	1.4
Barley Jaipur (Dec 20)	2128.5	0.4
Paddy-Basmati-Karnal (Dec 20)	3201.0	0.0
Discount over spot price (In %)		
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (Dec 20)	7500.0	-2.2
Soy Bean Indore (Dec 20)	4350.0	-2.0
Crude Palm Oil Kandl (Dec 31)	735.8	-1.6
Jeera Unjha (Jan 20)	16150.0	-1.3
Moong-Merta City (Dec 20)	6902.0	-0.7
Maize-Sangli (Dec 20)	2101.0	-0.7

कल का हाजिर भाव

औद्योगिक

Metals	Mumbai
Aluminium utensil scrap /kg	98........(98)
Aluminium ingots /kg	136........(136)
Brass sheet cutting /kg	321........(320)
Brass utensil scraps/kg	306........(306)
Copper heavy scrap /kg	425........(424)
Copper utensil scraps/kg	400........(398)
Copper wire bar /kg	458........(456)
Lead ingots /kg	158........(158)
Nickel Cathodes /kg	1050........(1030)
Tin slabs /kg	1285........(1285)
Zinc slabs /kg	185........(185)

Source:Bombay Metal Exchange

Cotton	Mumbai
Bengal Deshi /Qtl	10714........(10714)
DCH - 32 /Qtl	11220........(11220)
Jaydhar /Qtl	10039........(10039)
Shankar- 6 /Qtl	11023........(11023)

Source:Cotton Association of India

Oil	Mumbai
Castor FSG /10kg	926........(925)
Castor Comm /10kg	916........(915)
Ricebran oil/10kg	760........(760)
Groundnut oil /10kg	1115........(1120)
Linseed oil /10kg	900........(900)
Karanji /10kg	780........(780)
Palm oil /10kg	795........(795)
Sunflower exp ref /10kg	880........(875)
Sunflower oil exp /10kg	850........(845)
Soyabean ref / 10kg	875........(870)

Source:Bombay Commodity Exchange

सॉफ्ट

Sugar	Mumbai
Mumbai M-30 /Qtl	3282-3602 ....(3332-3590)

Source:Bombay Sugar Merchants Association

ऊर्जा

Crude Brent-$/Barrel	
NYSE Crude	60.93........(61.18)
Brent Crude (UK)	67.36........(67.73)
Brent Crude (WTI)	61.22........(61.22)
NYSE Natural Gas-$/Mmbtu (2.27)	........2.32
Furnace/ 180 Cst &/bbl	305.48........(281.47)
Naptha spot /Rs/MT	45170........(45170)
LSHS spot/ M.T.	36150........(36150)
Furnace Oil spot/ K.L.	33950........(33950)

Source:Petroleum Bazaar.com

सर्राफा

Gold	Mumbai
Standard (99.50 Purity) /10 gms	37968........(37877)
Pure (99.90 Purity) /10 gms	38121........(38029)
Silver.999/ kg	44250........(43975)

Source:India Bullion & Jewellers Association

@SPOT PRICE(MCX, NCDEX & ICEX)

Commodity	Unit	PClose	Price (₹.) Close
29 mm Cotton-Rajkot (N)	1 B	18718.25	18808.90
Alumini-Mumbai (M)	1 K	138.95	140.00
Bajra-Delhi (N)	1 Q	2050.00	2050.00
Bajra-Jaipur (N)	1 Q	1435.00	1999.15
Barley Jaipur (N)	1 Q	2128.00	2120.70
Brass-Jamnagar (M)	1 K	312.90	312.90
Cardamom-Vand. (I)	1 K	3233.00	3267.00
Castor Seed Disa (N)	1 Q	4422.70	4427.50
Castor Seed-Kadi (N)	X	4355.00	4355.00
Chana Bikaner (N)	1 Q	4367.75	4364.50
Chana Delhi (N)	1 Q	4562.50	4580.85
Chana-Akola (N)	X	4450.00	4400.00
Coriander-Gondal (N)	X	6550.00	6600.00
Coriander-Jaipur (N)	X	6932.50	6871.25
Coriander-Kota (N)	1 Q	6883.60	6871.35
Cotton Seed Oilck Ak (N)	1 Q	2120.10	2144.15
Cotton Seed Oilck Ka (N)	1 Q	2122.90	2169.05
Cotton-Kadi (N)	1 B	18644.55	18668.45
CPO-Kandla (M)	10 K	730.80	739.00
Crude Palm Oil Kandl (N)	10 K	734.40	747.75
Diamond 0.3 - Surat (I)	1 CT	889.10	895.00
Diamond 0.5-Surat (I)	1 CT	1540.35	1545.90
Diamond 1-Surat (I)	1 CT	3445.40	3448.75
Gold Ahm (M)	10 G	37882.00	37957.00
Gold Guinea-Ahmedaba (M)	8 G	30427.00	30488.00
Gold Petal-Mumbai (M)	1 G	3801.00	3810.00
Guar Gum 5 MT-Jodhpu (N)	X	7478.15	7667.50
Guar Seed 10 MT-Jodh (N)	1 Q	4046.50	4103.15
Guarseed-Jodhpur (I)	1 Q	3988.00	4025.00
Gur Muzaffar Nagar (N)	40 K	1196.45	1204.90
Isabgulseed-Unjha (I)	1 K	94.10	94.10
Jeera Jodhpur-Jodhpu (N)	X	16600.00	16850.00
Jeera Unjha (N)	1 Q	16354.55	16354.55
Kapas Kadi-Kadi (N)	X	1036.40	1041.00
Kapas-Rajkot (N)	X	1033.95	1041.80
Lead Mum (M)	1 K	154.85	152.90
Maize Kharif-Nizamab (N)	X	2075.00	2052.20
Maize Rabi-Gulabbagh (N)	1	2367.10	2390.70
Maize-Erode (N)	X	2082.50	2083.35
Maize-Feed/Ind-Delhi (N)	1 Q	2250.00	2250.00
Maize-Sangli (N)	X	2100.45	2115.40
Moong-Merta City (N)	1 Q	6900.00	6950.00
Mustardseed Alwar (N)	20 K	4694.50	4720.25
Nickel Mumbai (M)	1 K	1039.00	1045.30
Paddy-Basmati-Karnal (I)	1 Q	3171.00	3197.00
Paddy-Basmati-Karnal (N)	X	3200.00	3200.00
Pepper-Ernakulam (I)	1 K	356.60	353.60
Pepper-Kochi (N)	1 Q	35766.65	35550.00
Rape mustards-Patan (I)	20 K	829.00	818.00
Rapeseed Must.Seed (N)	X	2042.20	2035.00
RBD Palm Olein Kakin (N)	10 K	800.00	805.00
Ref Soya Oil Indore (N)	10 K	883.30	896.80
Ref Soya Oil Mum (N)	10 K	871.40	884.55
Ref Soya Oil Nagpur (N)	10 K	893.75	909.25
Rubber-Kochi (N)	1 Q	13100.00	13100.00
Rubber-Kochi/Ernak. (I)	1 Q	13121.00	13125.00
Silver M-Ahemdabad (M)	1 K	43978.00	44222.00
Soy Bean Indore (N)	1 Q	4350.00	4437.00
Soy Bean Kota (N)	1 Q	4254.65	4343.00
Soy Bean Nagpur (N)	1 Q	4393.50	4403.60
Soy Bean-Akola (N)	X	4353.00	4384.00
Soymeal Indore (N)	1 T	35256.00	35600.00
Soyoil-Indore (I)	10 K	878.40	897.00
Steel Long-Ghaziabad (I)	1 T	28520.00	28620.00
Steel Long-MGG (I)	1 T	29300.00	29300.00
Steel Long-Raipur (I)	1 T	26840.00	26750.00
Sugar M Delhi (N)	1 Q	3245.00	3295.00
Sugar M Grade-Kanpur (N)	1 Q	3323.80	3333.35
Sugar M Grade-Kolhap (N)	1 Q	3281.45	3266.80
Sugar M Kolkatta (N)	1 Q	3433.35	3438.10
Sugar M Muzaff (N)	1 Q	3250.00	3250.00
Sugar S-Kolhapur (N)	1 Q	3129.10	3100.00
Turmeric Nizamabad (N)	1 Q	6047.75	6047.75
Wheat Delhi (N)	1 Q	2270.00	2270.65
Wheat Kota (N)	1 Q	2147.00	2144.00
Wheat New Indore (N)	1 Q	2225.00	2225.00
Wheat New Kanpur (N)	1 Q	2080.00	2110.00
Wheat New-Rajkot (N)	1 Q	2200.00	2190.00
Yellow Peas Mum (N)	1 Q	4937.25	4937.25
Zinc Mumbai (M)	1 K	184.60	185.15

* as on Dec 19, 19

(M) MCX ,(N) NCDEX & (I) ICEX Spot prices

जिंस वायदा

DAY SESSION

दिवस सत्र (शुक्रवार)
कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19090, 19190, 19090, 19150	2100	341	5383
Jan 31	19290, 19420, 19290, 19380	2929	438	6020
Feb 28	19560, 19600, 19560, 19590	208	23	463
CottonSeed Oil-Akola NCDEX(1 Q)				
Dec 20	2113, 2154, 2110, 2135	580	27	870
Jan 20	2121, 2182, 2081, 2168	66370	4479	65740
Feb 20	2154, 2202, 2134, 2188	17200	1452	33440
Mar 20	2171, 2215, 2154, 2206	2060	181	3760
Apr 20	2180, 2200, 2175, 2200	140	12	150
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1107.5, 1113.5, 1107, 1108.5	412	61	840
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1109, 1114, 1104, 1111	1592	877	4033
Grains				
Bajra NCDEX(1 Qtl)				
Jan 20	1990, 2050, 1990, 2050	60	4	50
Guar Seed 10 NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4204, 4206, 4120, 4180	280	24	100
Jan 20	4206, 4236, 4132, 4146	59120	6673	80760
Feb 20	4244, 4278, 4178, 4190	13440	1844	18110
Mar 20	4248, 4248, 4248, 4248	50	2	35
Oil and Oilseeds				
CastorSeed New-Disa NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4392, 4392, 4310, 4324	560	35	1265
Jan 20	4388, 4400, 4344, 4350	6445	762	29050
Feb 20	4410, 4418, 4352, 4360	2520	302	5730
Mar 20	4380, 4382, 4340, 4374	485	52	5485
Apr 20	4350, 4384, 4330, 4352	320	56	470
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	744, 744, 736, 737.4	6730	548	24070
Jan 31	750, 750, 739.9, 741.6	13530	942	48500
Feb 28	750.1, 752, 742.7, 743	1810	141	8790
Mentha Oil MCX(1 K)				
Dec 31	1292.9, 1297.1, 1286.1, 1288.4	76.68	188	236.52
Jan 31	1297, 1302, 1295, 1298.3	11.16	29	101.16
Mustard Seed Rape Oil NCDEX(1 Q)				
Jan 20	4600, 4625, 4587, 4605	12110	873	19640
Feb 20	4578, 4600, 4567, 4592	750	63	2010
Apr 20	4507, 4560, 4506, 4530	4070	309	7890
May 20	4500, 4535, 4500, 4535	70	7	390
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Dec 20	887.6, 887.6, 886, 887	2405	70	4325
Jan 20	909.8, 911.8, 903, 904	32805	3228	56615
Feb 20	900, 904, 894.6, 897.8	10275	927	37945
Mar 20	887.4, 890.4, 885, 889.8	770	69	5980
Apr 20	884.8, 884.8, 884.8, 884.8	5	1	5
Soyabean Indore NCDEX(1 Q)				
Dec 20	4374, 4374, 4350, 4350	55	8	60
Jan 20	4340, 4380, 4326, 4338	48505	5327	161055
Feb 20	4390, 4406, 4352, 4362	17550	2238	131035
Mar 20	4416, 4440, 4388, 4396	4985	670	40150
Apr 20	4452, 4482, 4430, 4444	935	157	3765
Others				
GuarGum 5T-Jodhpur NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	-, 7500, -, 7500	30	3	60
Jan 20	7644, 7735, 7542, 7576	16410	2598	57390
Feb 20	7740, 7838, 7650, 7674	4770	806	11975
Mar 20	7834, 7854, 7770, 7770	50	6	115
Pulses				
Chana-Bikaner NCDEX(1 Qtl)				
Dec 20	4450, 4525, 4450, 4506	190	18	590
Jan 20	4477, 4486, 4448, 4466	12750	1051	45400
Mar 20	4424, 4441, 4400, 4417	2310	206	4900
Apr 20	4420, 4421, 4400, 4400	70	4	390
Spices				
Cardamom MCX(1 K)				
Jan 15	3170.2, 3300, 3162.6, 3213.2	1.3	13	10.6
Feb 14	3075, 3170, 3040.1, 3151.5	1.9	19	3.5
Coriander-Kota NCDEX(1 Q)				
Dec 20	7000, 7180, 6807, 6988	2870	184	640
Jan 20	6419, 6514, 6281, 6383	4280	381	9680
Apr 20	6801, 6948, 6750, 6807	1040	93	5020
Jeera Unjha NCDEX(1 Q)				
Jan 20	15970, 16210, 15870, 16150	1107	322	2277
Mar 20	15690, 15945, 15690, 15875	210	69	375
Apr 20	15590, 15640, 15450, 15580	39	13	69
Turmeric Nizamabad NCDEX(1 Q)				
Dec 20	6180, 6256, 6050, 6134	400	43	200
Mar 20	6282, 6290, 6068, 6096	2580	422	6990
Apr 20	6168, 6168, 6000, 6022	640	116	3035

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	134.55, 134.55, 134.1, 134.4	2510	420	7570
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	134.65, 134.65, 134.1, 134.45	1564	1264	2998
Jan 31	135.25, 135.45, 134.85, 135.3	966	576	2254
Feb 28	136.05, 136.05, 134.65, 135.35	2	2	2
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	445.5, 445.5, 442.9, 443.6	14297.5	4779	13262.5
Jan 31	450.3, 450.5, 448, 448.9	2045	693	3952.5
Feb 28	454.1, 454.1, 453.2, 453.65	5	2	72.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.2, 153.4, 152.8, 152.95	3945	663	4375
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.4, 153.4, 152.85, 152.95	1737	1512	2057
Jan 31	152.4, 152.4, 152.1, 152.2	197	183	2271
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1036.3, 1038.8, 1031.1, 1037	9360	5535	2829
Jan 31	1037.4, 1038.3, 1030.2, 1036.4	465	253	550.5
Feb 28	1039.3, 1039.3, 1039.3, 1039.3	1.5	1	4.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.55, 183.55, 182.6, 183	12140	1947	12260
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183.6, 183.6, 182.55, 182.85	4448	3495	5307

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Jan 31	182.3, 182.45, 181.9, 182.1	1165	785	8400
Feb 28	181.55, 181.55, 181.55, 181.55	1	1	26
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	38040, 38084, 37976, 37999	4.17	3496	16.01
Apr 03	38080, 38145, 38044, 38061	0.14	128	3.91
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30500, 30540, 30500, 30527	0	92	0
Jan 31	30465, 30550, 30465, 30479	0	69	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	38076, 38100, 37982, 38013	0.48	3969	0.82
Feb 05	38043, 38089, 37990, 38006	0.12	1032	0.32
Mar 05	38040, 38055, 37980, 38045	0	6	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3867, 3870, 3857, 3860	0	447	0.01
Jan 31	3850, 3852, 3836, 3844	0	189	0
Feb 28	3831, 3831, 3831, 3831	0	1	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44627, 44789, 44580, 44614	164.94	4559	374.31
May 05	45069, 45213, 45052, 45150	1.14	37	6.03
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44800, 44850, 44603, 44650	19.94	13682	30.92
Apr 30	45141, 45299, 45072, 45116	0.93	691	1.94
Jun 30	45600, 45650, 45600, 45625	0	2	0.01
Aug 31	47399, 47399, 47399, 47399	0	1	0.01
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44740, 44804, 44604, 44642	61.31	9629	53.65
Apr 30	45146, 45273, 45067, 45112	0.64	125	2.13

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	161.4, 165.8, 161.4, 165.1	62023mb	28473	27378mb
Jan 28	162.9, 165.8, 162.8, 165	9735mb	4785	16630mb
Feb 25	159.1, 162, 159.1, 161.5	638mb	466	4103mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Jan 17	4360, 4364, 4331, 4335	7506bl	45113	3694bl
Feb 19	4358, 4362, 4331, 4336	131bl	1053	70bl

सायं सत्र (गुरुवार)
कृषि जिंस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Cotton				
Cotton MCX(1 B)				
Dec 31	19060, 19190, 19040, 19130	4171	704	5736
Jan 31	19280, 19400, 19270, 19330	2606	441	5506
Kapas MCX(20 K)				
Apr 30	1092, 1109, 1091, 1108.5	308	61	592
Shankar Kapas-Rajkot NCDEX(20 Kg)				
Apr 30	1092.5, 1109, 1091.5, 1108.5	1841	1005	4062
Oil and Oilseeds				
Crude Palm Oil MCX(10 K)				
Dec 31	725.2, 743, 722, 740.5	16140	1258	24640
Jan 31	729, 748, 725, 746.3	26250	1777	48170
Feb 28	728.8, 750.7, 727, 749.2	4790	384	8670
Mar 31	744, 744, 744, 744	10	1	10
Ref Soy Oil-IDR-2016 NCDEX(10 Kg)				
Jan 20	885.8, 906.6, 882.8, 905.6	41855	4332	55250
Feb 20	877, 898.8, 877, 897.8	20760	1715	35760
Mar 20	870.2, 885, 870, 885	5850	306	5500

धातु

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Metal- non ferrous				
Aluminium MCX(1 K)				
Dec 31	133.8, 134.7, 133.6, 134.45	7650	1177	7715
Aluminium Mini MCX(1 K)				
Dec 31	133.7, 134.7, 133.55, 134.45	3780	3108	2671
Jan 31	134.3, 135.4, 134.15, 135.15	896	715	1535
Copper MCX(1 K)				
Dec 31	442.6, 446.05, 441.7, 445.7	28597.5	9494	12772.5
Jan 31	447.3, 451.2, 446.7, 450.85	2107.5	787	3330
Feb 28	452.75, 454.85, 452.75, 453.75	10	4	67.5
Lead MCX(1 K)				
Dec 31	153.7, 153.75, 153, 153.15	12395	2004	3720
Lead Mini MCX(1 K)				
Dec 31	153.6, 153.7, 153, 153.15	5517	4637	1652
Jan 31	152.35, 152.45, 152.1, 152.2	717	593	2236
Nickel MCX(1 K)				
Dec 31	1012.5, 1039.1, 1011, 1036.5	26242.5	15552	1480.5
Jan 31	1011.8, 1038.3, 1009.3, 1035.6	1464	942	535.5
Zinc MCX(1 K)				
Dec 31	183.65, 184.05, 183.05, 183.7	30655	4853	10265
Zinc Mini MCX(1 K)				
Dec 31	183.4, 183.8, 182.85, 183.4	10391	8050	4472
Jan 31	182.45, 182.75, 181.85, 182.45	2431	1635	8322
Metal- precious				
Gold MCX(10 G)				
Feb 05	37959, 38130, 37860, 38109	10.52	8772	15.44
Apr 03	38001, 38180, 37920, 38161	0.54	460	3.81
Gold Guinea MCX(8 G)				
Dec 31	30534, 30550, 30513, 30529	0	209	0
Jan 31	30474, 30538, 30407, 30518	0	143	0
Gold Mini MCX(10 G)				
Jan 03	37998, 38140, 37880, 38110	1.31	10966	0.73
Feb 05	37950, 38136, 37880, 38111	0.27	2330	0.31
Mar 05	37936, 38109, 37890, 38092	0	33	0.01
Gold Petal MCX(1 Gm)				
Dec 31	3856, 3875, 3846, 3869	0	1101	0.01
Jan 31	3844, 3853, 3830, 3848	0	419	0
Feb 28	3835, 3837, 3815, 3830	0	8	0
Silver MCX(1 K)				
Mar 05	44511, 44839, 44263, 44796	512.85	13763	333.6
May 05	44975, 45297, 44787, 45257	3.21	105	6.18
Silver Micro MCX(1 K)				
Feb 28	44475, 44850, 44302, 44817	59.24	39455	26.3
Apr 30	45000, 45293, 44805, 45258	2.18	1726	1.81
Silver Mini MCX(1 K)				
Feb 28	44507, 44850, 44295, 44818	179.25	28053	40.94
Apr 30	45068, 45292, 44799, 45261	1.96	374	2.07

तेल एवं गैस

Maturity	Open, High Low Close	Qty	Trds	OI
Gas				
Natural Gas MCX(1 MB)				
Dec 26	162.9, 163.9, 159.2, 160.7	176408mb	82534	25684mb
Jan 28	162, 163.2, 159.2, 161	20433mb	11477	16853mb
Feb 25	159.5, 160.3, 157.2, 158.1	1750mb	1295	4151mb
Oil				
Crude Oil MCX(1 BL)				
Jan 17	4324, 4372, 4313, 4360	21088bl	127069	2781bl
Feb 19	4320, 4366, 4312, 4355	351bl	2865	52bl

g-grams, k-kilograms, q-quintals, t-tonnes, b-bales,bl-barels,mb-mmBTU,m-Mnd; Quantity & Open interest in tonnes except for crude oil and natural gas; For Gas is '000 mmBTU & for crudeoil in '000 barrel; Market price in ₹.

प्रदर्शन की आग तेज यूपी में 6 की मौत

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ शुक्रवार को दिल्ली में आयोजित एक रैली के दौरान वाहन में लगी आग बुझाने का प्रयास करते पुलिसकर्मी *फोटो : पीटीआई*

अर्चिस मोहन और अभिषेक रक्षित

देश भर में लगातार छठे दिन भी नागरिकता संशोधन विधेयक और राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) को लेकर व्यापक विरोध प्रदर्शन जारी रहा। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) शासित उत्तर प्रदेश को छोड़कर शुक्रवार को देश के ज्यादातर हिस्से में विरोध शांतिपूर्ण रहा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन से जुड़ी हिंसा और पुलिस कार्रवाई के बीच छह लोगों की मौत हो गई। समाजवादी पार्टी (सपा) ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पुलिस को लोगों के घर में घुसकर परेशान करने का आदेश दे रही है। शुक्रवार को भाजपा को एक और झटका तब लगा जब जनता दल (यूनाइटेड) और लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने सार्वजनिक तौर पर एनआरसी को लेकर अपना एतराज जताया। बिहार के मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे पर कहा, 'काहे का एनआरसी? बिल्कुल लागू नहीं होगा।'

सहयोगी दलों का एतराज

वहीं लोजपा प्रमुख चिराग पासवान ने कहा कि देश भर में हो रहे प्रदर्शन से यह पता चलता है कि सरकार समाज के एक अहम तबके के बीच बनी भ्रम की स्थिति को रोकने में नाकाम रही है। पासवान ने एक पत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से यह गुजारिश की थी कि इस विवादास्पद प्रस्ताव पर सत्तासीन राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की एक बैठक बुलाई जाए। जद(यू) और लोजपा ने संसद में नागरिकता संशोधन कानून का समर्थन किया था। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने टेलीविजन चैनलों के लिए एक चेतावनी जारी करते हुए उन्हें ऐसे कंटेंट दिखाने से मना किया जिससे हिंसा भड़क सकती है। इसने 11 दिसंबर को भी ऐसी ही चेतावनी जारी की थी।

पुराने दस्तावेज नहीं

गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि किसी भी भारतीय को उसके माता-पिता या दादा-दादी के 1971 से पहले के जन्म प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज दिखाकर नागरिकता साबित करने के लिए नहीं कहा जाएगा और न ही उसे नाहक परेशान किया किया जाएगा। अपने ट्वीट में गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि बिना किसी दस्तावेज वाले निरक्षर नागरिकों को गवाह या समुदाय के सदस्यों से समर्थित सबूतों पेश करने की अनुमति होगी।

प्रवक्ता ने कहा, 'भारत की नागरिकता जन्मतिथि या जन्मस्थान या दोनों से संबंधित कोई दस्तावेज पेश कर साबित की जा सकती है। ऐसी सूची में ढेर सारे आम दस्तावेज होने की संभावना है ताकि कोई भी भारतीय नाहक परेशान न हो या वह मुश्किलों में नहीं आए।' प्रवक्ता ने कहा, 'भारतीय नागरिकों को 1971 से पहले का अपने माता-पितादादा-दादी के पहचान पत्र, जन्मप्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों को पेश कर अपने पुरखों को साबित नहीं करना होगा।' राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एक टीम गठित कर जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय में पुलिस द्वारा रविवार शाम को की गई ज्यादतियों की जांच करने की पहल की है। वहीं कोलकाता में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा कानून के जरिये हिंसा की घटनाओं को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने एक रैली में कहा, 'भाजपा लोगों को नागरिकता देने वाली कौन होती है? वह जो कहती है उस पर आप ध्यान न दें। भाजपा की वजह से ही पूरा देश जल रहा है।'

राजधानी दिल्ली में भी हजारों मुसलमानों ने सीलमपुर, जामा मस्जिद और दरियागंज क्षेत्रों में आयोजित विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। शाम होते ही यहां भी हिंसक प्रदर्शन शुरू हो गए जिसके बाद पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा। दिल्ली के दरियागंज इलाके में नए कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान एक कार को आग के हवाले कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली गेट पर प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में बाहरी लोग शामिल थे।

कानून भेदभावपूर्ण

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून भेदभावपूर्ण है और प्रस्तावित एनआरसी के कारण नोटबंदी की तरह एक बार फिर लोगों को अपनी एवं अपने पूर्वजों की नागरिकता साबित करने के लिए कतार में खड़ा होना होगा। देश के विभिन्न हिस्सों में जारी विरोध प्रदर्शन के बीच कांग्रेस अध्यक्ष ने एक वीडियो संदेश में कहा, 'लोकतंत्र में लोगों को सरकार के गलत फैसलों एवं नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने का अधिकार है। सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह लोगों की आवाज एवं उनकी चिंताओं पर ध्यान दे। लेकिन भाजपा सरकार लोगों की आवाज का निरादर कर रही है और बल प्रयोग कर उसे दबाने का प्रयास कर रही है।

सुझाव सुनेगी सरकार

सरकार के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि अगर संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों के पास कोई सुझाव है तो सरकार उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। केंद्रीय गृह मंत्रालय संशोधित नागरिकता कानून (सीएए) के लिए विधि मंत्रालय के साथ मिलकर नियम तैयार कर रहा है।

साथ में एजेंसियां

मोबाइल-इंटरनेट पर रोक

देश भर में विरोध से पर्यटन क्षेत्र में मंदी की आशंका

अनीश फडणीस

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन की वजह से विदेशी पर्यटकों के आने की तादाद में कमी दिखने लगी है। इस साल के पहले 10 महीने में पर्यटन क्षेत्र में 3 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है और पर्यटन परिचालकों को डर है कि आगे भी इस तादाद में कमी दिख सकती है।

विदेशी पर्यटक अपनी भारत यात्रा रद्द कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन हिंसक होने की वजह से पूर्वोत्तर राज्यों की यात्रा पर जाने वाले लोगों ने अपनी यात्रा रद्द करा दी है। इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कोहली कहते हैं, 'इस साल बुकिंग भी काफी कम हुई है। एक के बाद एक बुरी खबर सुनने को मिल रही है लेकिन सरकार की तरफ से स्थिति नियंत्रित करने की कोशिश की गई।'

देश में विदेशी पर्यटकों के आने के लिहाज से दिसंबर सबसे व्यस्तता वाला महीना रहता है लेकिन इस बार पर्यटक परिचालकों को आशंका है कि पर्यटक कम ही आएंगे। स्टिक ट्रैवल्स के अध्यक्ष सुभाष गोयल का कहना है, 'हम दिसंबर में 7-8 फीसदी वृद्धि की उम्मीद करते थे लेकिन अब पर्यटक भारत आने से हिचक रहे हैं। ऐसे में मुमकिन है कि इस वृद्धि में 2-3 फीसदी की कमी दिखे।' व्यापक विरोध-प्रदर्शन की वजह से कई देशों की सरकारों ने भी चेतावनी जारी की है, इसी वजह से लोगों ने पूर्वोत्तर राज्यों में जाने की योजना रद्द कर दी है।

रूस, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और इजरायल जैसे देशों ने अपने नागरिकों को विशेषतौर पर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा करने पर सतर्कता बरतने की सलाह दी है। कनाडा ने भी अपने नागरिकों को चेताया है कि अगर ज्यादा जरूरी न हो तो असम और इसके पड़ोसी राज्यों में यात्रा करने से बचें। गोयल कहते हैं, 'हम विदेश के अपने साझेदारों को आश्वस्त कर रहे हैं। पर्यटन और विदेश मंत्रालय को भी विदेशी सरकारों से जमीनी हकीकत साझा करनी चाहिए।'

जनवरी-अक्टूबर के बीच भारत आने वाले पर्यटकों की तादाद 85 लाख है और इसमें सालाना आधार पर 2.7 फीसदी की वृद्धि हुई है। वर्ष 2018 में पर्यटकों की तादाद में 5.2 फीसदी की वृद्धि हुई और यह 1 करोड़ तक रहा। हालांकि 2019 में इस वृद्धि में कमी आई।

कोहली का मानना है कि देश भर में प्रदर्शन का असर पर्यटन पर पड़ेगा लेकिन यह असर लंबे समय के लिए नहीं होगा। वह कहते हैं, 'पर्यटकों की सुरक्षा पर कोई खतरा नहीं है और यह विरोध-प्रदर्शन भी शहर के किसी खास हिस्से तक ही सीमित है।'रिफंड और यात्रा की तारीख में फेरबदल की योजना के लिए विमानन कंपनियों और होटलों के साथ तालमेल बिठाने के साथ-साथ पर्यटन परिचालकों की अच्छी-खासी मौजूदगी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भी है।

एफसीएम ट्रैवल सॉल्युशंस के प्रबंध निदेशक रक्षित देसाई का कहना है, 'हम ग्राहकों के अनुभव को लेकर चिंतित हैं और हमारी कोशिश यह है कि हम मेहमानों के आने और जाने तक उनका पूरा ख्याल रखें। हमने अधिकारियों से इस बाबत संपर्क साधने की कोशिश की है कि वे कुछ अहम हवाईअड्डे पर हमारी मौजूदगी सुनिश्चित करें ताकि ग्राहकों की हम पूरी मदद कर सकें।' ट्रेल ब्लेजर टूअर्स इंडिया के मुख्य कार्यकारी होमा मिस्त्री कहते हैं, 'हमारे लिए यह सीजन कमाई वाला होता है और हमें उम्मीद है कि हालात सामान्य होंगे। हमें अभी तक यात्रा रद्द करने की कोई सूचना नहीं है।'

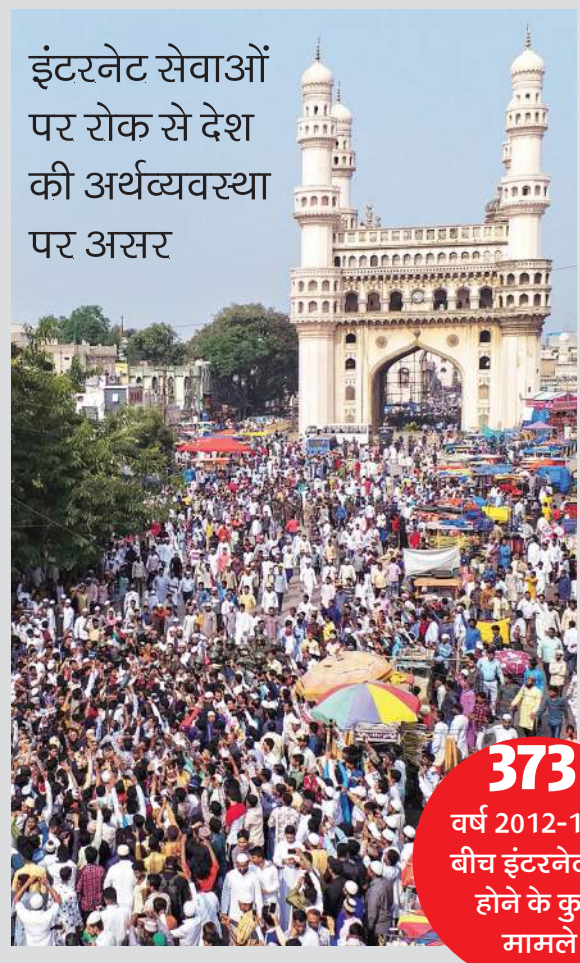

नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के चलते कई जगहों पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गईं। इससे पहले भी राज्य सरकारों ने 'कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए' या फर्जी खबरों पर रोक लगाने के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं। लेकिन यह पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर इंटरनेट सेवाओं को रोक दिया गया।

इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनैशनल इकनॉमिक रिसर्च द्वारा पिछले साल जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इंटरनेट पर रोक लगाने से साल 2012-2017 के बीच प्रत्येक एक घंटे के शटडाउन में औसतन 1,86,332 डॉलर का नुकसान हुआ। रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया कि भारत में कुल 16,315 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद की गईं, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को करीब 3.04 अरब डॉलर का नुकसान हुआ।

गैर-लाभकारी संगठन सॉफ्टवेयर **फ्रीडम लॉ सेंटर** द्वारा संकलित आंकड़े:

सालाना आधार पर आंकड़े

2012	3
2013	5
2014	6
2015	14
2016	31
2017	79
2018	134
2019*	101

राज्यों के आधार पर...

जम्मू-कश्मीर	180	त्रिपुरा	5
राजस्थान	67	मणिपुर	5
उत्तर प्रदेश	25	ओडिशा	5
हरियाणा	13	मध्य प्रदेश	5
गुजरात	11	अरुणाचल प्रदेश	4
बिहार	11	असम	3
महाराष्ट्र	10	नागालैंड	3
पश्चिम बंगाल	9	उत्तराखंड	2
मेघालय	5		

**अभी तक*

भारत में सबसे अधिक समय तक इंटरनेट बंद के मामले

1 कश्मीर (4 अगस्त 2019 से --) 136 दिन और अभी जारी

2 कश्मीर (8 जुलाई 2016 से 19 नवंबर 2016) -133 दिन

3 दार्जिलिंग (18 जून 2017 से 25 सितंबर 2017) - -100 दिन

आईआईएम बेंगलूरु में विरोध

फोटो: बीएस

नागरिकता संशोधन कानून, एनआरसी और बेंगलूरु में धारा 144 लगाए जाने के विरोध में गुरुवार को भारतीय प्रबंध संस्थान-बेंगलूरु के छात्रों ने सांकेतिक तौर पर विरोध प्रदर्शन जताते हुए परिसर के बाहर अपने जूते रखे

झारखंड में झामुमो गठबंधन आगे

शुक्रवार को 81 सीटों वाले झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए पांचवे और अंतिम चरण के मतदान के साथ चुनाव संपन्न हो गया। मतदान के बाद हुए एक्जिट पोल में त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनती नजर आई। एक्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेतृत्व वाला गठबंधन आगे है जबकि रघुवर दास के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सरकार बहुमत के आंकड़े से पिछड़ सकती है।निर्वाचन आयोग के अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार शाम 5 बजे तक विधानसभा की 16 सीटों के लिए अंतिम चरण में कुल 70.83 प्रतिशत मतदान हुआ है।

इंडिया टुडे-एक्सिस एक्जिट पोल के मुताबिक भाजपा झारखंड विधानसभा में 22 से 32 सीटें जीत सकती है। जबकि जेएमएम, कांग्रेस और राजद का गठजोड़ 38-50 सीटें जीत सकता है। वहीं झारखंड विकास मोर्चा को 2-4 सीटें मिल सकती हैं। आजसू के खाते में 3-5 सीटें आ सकती हैं जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार 4-7 सीटें जीत सकते हैं। टाइम्स नाऊ एक्जिट पोल के मुताबिक जेएमएम गठबंधन 44 सीटें जीत सकता है जबकि भाजपा 28 सीटें जीत सकती है। आईएएनएस-सीवोटर-एबीपी एक्जिट पोल ने जेएमएम गठबंधन के लिए 31-39 सीटों, जबकि भाजपा के खाते में 28-36 सीटें रहने की संभावना जताई है। *बीएस*

पेप्सी ने थामा 'दबंग' सलमान खान का हाथ

कोला क्षेत्र की दिग्गज कंपनी पेप्सी ने विवादास्पद लेकिन लोकप्रिय अभिनेता सलमान खान को अपने ब्रांड का चेहरा बनाने का फैसला किया है जिनकी नई फिल्म दबंग 3 रिलीज हुई है। अब वक्त ही तय करेगा कि यह कंपनी का रणनीतिक कदम है या फिर कोई बड़ी भूल

टी ई नरसिम्हन

बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता सलमान खान अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दबंग' शृंखला की फिल्म 'दबंग 3' के रिलीज होने के साथ एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। 50 से अधिक उम्र के हो चुके सलमान अब कोला ब्रांड पेप्सी का चेहरा होंगे। फिल्मी पर्दे से इतर भी कई विवादों की वजह से बड़े उपभोक्ता ब्रांडों ने सलमान से परहेज करने की कोशिश की है। यहां तक कि थम्स अप ही आखिरी कोला ब्रांड था जो उनसे जुड़ा था लेकिन करीब तीन साल पहले इस कंपनी ने भी अक्षय कुमार का दामन थाम लिया। हालांकि वह लगातार तीन सालों तक वह फोर्ब्स की सूची में ब्रांडों से सबसे ज्यादा पैसा पाने वाले सेलेब्रिटी में शामिल रहे हैं लेकिन इस साल वह इस कतार में नहीं हैं और उनकी जगह अब अक्षय कुमार ने ले ली है। फिलहाल वह गृह साज-सज्जा और इनर वियर जैसे श्रेणियों के आठ ब्रांड से जुड़े हैं।

सलमान के लिए बढ़ता लगाव

पेप्सिको इंडिया के एक प्रवक्ता का कहना है कि उनकी शहरी बिंदास छवि की वजह से यह करार उनके पक्ष में गया है। ब्रांड पेप्सी के हाल के विज्ञापनों और सलमान में बिंदासपन ही एक सामान्यता है। हालांकि सभी विशेषज्ञ इस बात की ओर इशारा करते हैं कि उनकी फिल्म 'दबंग 3' का असर हो सकता है। इस फिल्म की पहली शृंखला वाली फिल्में भी काफी सफल रही थीं और फिल्म का मुख्य किरदार चुलबुल पांडेय खासतौर पर लोगों में लोकप्रिय रहा। ऐसे में पेप्सी बॉक्स ऑफिस पर सफल रही इस कॉमिक फिल्म शृंखला पर दांव लगाने का मन बना चुकी है। एक मार्केटिंग और संचार एजेंसी मोगे इंडिया के संस्थापक संदीप गोयल कहते हैं कि यह चयन बेहद हैरान करने वाला और विवादास्पद था। लेकिन उनका कहना है कि कोला ब्रांड दरअसल ब्रांड सलमान के अक्खड़पन पर ही जोर देना चाहता है जिसे पेप्सी ने 20 साल पहले 'नथिंग ऑफिशियल अबाउट इट' के मंत्र के साथ जोड़ा था जब इसने क्रिकेट वर्ल्ड कप 1996 के आधिकारिक साझेदार के कोका कोला को निशाना बनाया था। वह कहते हैं, 'इसके अलावा उम्रदराज होते सलमान को चुनने की कोई वजह नहीं है क्योंकि हमारे विज्ञापन पेप्सी पीने वाले किशोर वर्ग को लक्षित करते हैं।'

गोयल कहते हैं कि सलमान को चुनने के पीछे रणनीतिक से ज्यादा तार्किक वजह हो सकती है। उन्होंने दबंग फिल्म में जिस तरह का किरदार निभाया था, उसे लोगों ने काफी पसंद किया और पेप्सी सलमान की शख्सियत के अनुरूप ही अपना विज्ञापन तैयार कर सकती है। बिजूर कंसल्ट के ब्रांड सलाहकार और संस्थापक कहते हैं, 'सलमान ने उम्र को पीछे छोड़ दिया है। पेप्सी ने सलमान के उस रुख पर अपनी मुहर लगाई है जिससे उनकी उम्र की बात पीछे छूट जाती है। उनका 'दबंग' रुख ही सबसे फिट है।'

कंपनी इस बात का खुलासा नहीं करती है कि उसने सलमान के साथ कितनी रकम में करार किया है। लेकिन कई लोगों का कहना है कि उनकी फीस की तुलना इस कारोबार के सभी शीर्ष ब्रांडों मसलन भारती क्रिकेट के कप्तान विराट कोहली के साथ की जा सकती है। कोहली 2017 तक पेप्सी का चेहरा थे लेकिन उन्होंने एक साक्षात्कार में इस बात की घोषणा कर दी कि वह कंपनी के हानिकारक फिजी ड्रिंक और फ्राइड स्नैक्स का विज्ञापन नहीं करेंगे जबकि उनके अनुबंध को लेकर दोबारा भी बातचीत जारी हुई थी। उसके बाद से कंपनी ने युवा अभिनेताओं को तरजीह देना शुरू कर दिया।

एक विशेषज्ञ का कहना है कि सलमान से ब्रांड की लोकप्रियता फिर से वास आएगी। उनकी शख्सियत में एक उदार व्यक्ति वाला एंगल है जो युवा ग्राहकों को अपील करता है। उनसे जुड़े विवाद की वजह से भी उनकी व्यापक अपील है जिससे पेप्सी को हिंदीभाषी क्षेत्रों में अपनी जगह बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने दबंग में जिस तरह का किरदार निभाया था उसे काफी लोग पसंद करते हैं। बिजूर का कहना है कि यह ब्रांड सलमान से ज्यादा 'दबंग-3' पर दांव लगा रहा है।

हालांकि पेप्सिको इंडिया के प्रवक्ता का कहना है कि सलमान को ब्रांड से जोड़ने की कवायद भी उसी रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत कलाकारों और नए उम्र के मशहूर लोगों को जोड़ा जाता है। उनका कहना है, '2020 में हम ब्रांड की, 'हर घूंट में स्वाग' के संदेश को सलमान के साथ पेश करेंगे।' ब्रांड से टाइगर श्रॉफ और दिशा पटनी भी इसके ब्रांड ऐंबेसडर के तौर पर जुड़े हैं। सलमान के पेप्सिको के साथ जुड़ने के साथ ही चर्चा शुरू हो गई है और यह देखने दिलचस्प होगा कि इस विवादास्पद चयन को लेकर आगे क्या होगा।

ब्रांड करार

ब्रांड	साल
पेप्सी	2019
भारत पे	
सोमानी सिरैमिक्स	
इमामी खाद्य तेल	2018
सीपी प्लस	2017
इमेज आइवियर	
रिलैक्सो की बहामास स्लिपर्स	2016
डिस्की स्कॉट	2015
एस्ट्रल पाइप्स	2014

पहले का करार:
माउंटेन ड्यू, थम्स अप, ऐपी फिज, पीएनजी ज्वैलर्स, येलो डायमंड चिप्स, स्प्लैश आदि